page 1 and 8 July 24_page 1 Mar 25 final ds.qxd 7/24/2026 1:50 AM Page 1

epaper.dehatsandesh.com

3 जम्मू इलाके के कुछ हिस्सों में बारिश का एक नया दौर शुरू

5 टी 20 में जीत की राह पर लौटने उतरेगा भारत, जिम्बाबे के खिलाफसीरीज में अयर की अग्निपरीक्षा

8 बारिश के बाद झेलम नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा लेकिन जलस्तर खतरे के निशान से नीचे

मौसम जम्मू — न्यूनतम 22 — अधिकतम 25

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-185 | जम्मू तवी, शुक्रवार 24 जुलाई, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

एलजी सिन्हा ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश

श्रीनगर, 23 जुलाई । जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा और मौसम की चुनौतियों के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने, खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवाद-विरोधी अभियानों को तेज करने और सुरक्षा से जुड़े नए खतरों को समय रहते खत्म करने का निर्देश दिया।

उपराज्यपाल ने हाल ही में खराब मौसम और इलाके में भारी बारिश को देखते हुए चल रही अमरनाथ यात्रा के लिए लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को बेहतर तालमेल बनाए रखने और बाबा बर्फानी के सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, भलाई और सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी सुविधाओं की विभाग-वार व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया, जिसमें फायर और इमरजेंसी सेवाओं, पावर ग्रिड और पानी की सप्लाई के बुनियादी ढांचे का कड़ाई से पालन करना शामिल है। उन्होंने अग्नि और आपातकालीन सेवाओं, पावर ग्रिड और जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के कड़े ऑडिट सहित सभी सुविधाओं की विभाग-वार समीक्षा करने का निर्देश

दिया। पहले 20 दिनों में 3,91,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के कारण 19 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा स्थगित है और इसका फिर से शुरू होना पूरी तरह से मौसम की स्थितियों पर निर्भर है। हाल ही में हुई भारी बारिश के मद्देनजर, सिन्हा ने बाढ़ सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और तीर्थयात्रा मार्गों के सभी नालों से तत्काल मलबा हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने चौबीसों घंटे आपदा प्रतिक्रिया तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने, स्वच्छ पटरियों और सुव्यवस्थित स्वच्छता सुविधाओं और राशन, एलपीजी, केरोसिन एवं आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करते हुए निरंतर परिचालन तत्परता की आवश्यकता पर बल दिया। सिन्हा ने अधिकारियों को मार्ग में अनधिकृत सेवा प्रदाताओं को सख्ती से प्रतिबंधित करने और 100 प्रतिशत अनिवार्य प्री-पेड सेवा प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया यह बैठक यह स्पष्ट करती है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन सुरक्षा खतरों से निपटने और प्राकृतिक आपदाओं के बीच श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दोहरे स्तर पर सतर्क है। एक ओर जहाँ आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य और सुरक्षा से कोई समझौता न करने की प्रतिबद्धता जताई गई हैं

नीट मुद्दे पर बहस से बचने के लिए विपक्ष शर्तें जोड़ रहा है : किरेन रिजिजू

नई दिल्ली, 23 जुलाई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा से बचने के लिए पूर्व शर्तें लगा रहा है। जब विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा, तब रिजिजू ने कहा कि इस मुद्दे पर होने वाली चर्चा के दौरान सरकार भी अपना पक्ष रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य जितनी देर चाहें, उतनी देर तक अपनी बात रख सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो इस विषय पर दो दिनों तक भी चर्चा कराई जा सकती है। रिजिजू ने यह भी कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा की तिथि और अवधि तय करने का अधिकार भी विपक्ष को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विषय पर चर्चा कराने के लिए

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से भी संपर्क किया है।रिजिजू ने यह टिप्पणी उस समय की, जब सदन की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई। नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर जारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जैसे ही सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे और तख्तियां प्लेकार्ड दिखाने लगे। कई सदस्य सदन के बीचोंबीच आ गए। उस समय पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से अपनी-अपनी सीटों पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना उचित नहीं है। हालांकि विरोध प्रदर्शन जारी रहने के कारण दिन के कार्यसूची में शामिल दस्तावेज सदन पटल पर रखे जाने के बाद लगभग दस मिनट के भीतर ही सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने प्रश्नकाल को दिन की सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही बताया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, **प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद सदन हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं सरकार से बात करूंगा और सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद चर्चा में भाग लें।** गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल बाधित रहे, क्योंकि विपक्षी दल नीट प्रश्नपत्र लीक विवाद पर चर्चा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। यह बैठक सदन में लगातार हो रहे गतिरोध और नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा की मांग के संबंध में हुई।

खबर संक्षेप

घर में घुसा तेंदुआ, 6 साल की बच्ची घायल

शोपियां, 23 जुलाई । गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां ज़िले के केलर इलाके में लैत्री वाली बेहक के जंगल वाले इलाके में एक घर में तेंदुआ घुस गया जिससे छह साल की एक बच्ची घायल हो गई।

एक अधिकारी ने बताया कि तेंदुआ केलर में एक घर में घुस गया और उसने बच्ची पर हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गई। उन्होंने बताया कि घायल बच्ची को तुरंत इलाज के लिए ज़िला अस्पताल शोपियां ले जाया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है। बाद में बच्ची की पहचान शोपियां के केलर में ज़राकान शलिदार के रहने वाले फारूक अहमद टेडवा की बेटी आफिया जान (6) के तौर पर हुई।

ईओडब्लू कश्मीर ने 2.5 करोड़ रुपये के शॉल धोखाधड़ी मामले में चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

श्रीनगर, 23 जुलाई । इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्लू) कश्मीर ने 2.5 करोड़ रुपये की कथित शॉल धोखाधड़ी के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मुनाफ़े का वादा करके एक व्यापारी से शॉल लिए और फिर उनका भुगतान नहीं किया।

ईओडब्लू द्वारा जारी एक बयान में प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कश्मीर ने एफआईआर नंबर 55/2022 के तहत (धारा 420, 120-बी और 201 आरपीसी) श्रीनगर की %सब-जज स्मॉल कॉज़ेस कोर्ट में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन पर इस मामले में शामिल होने का आरोप है।

उन्होंने बताया कि आरोपितों की पहचान अर्शीद अहमद शोरा उर्फ बिलाल पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रशीद शोरा निवासी पखरीबल बोटाकदल, लालबाज़ार श्रीनगर, फिरदौस अहमद मीर पुत्र अब्दुल रहमान मीर निवासी अबिकरपोरा रैनावाड़ी वर्तमान में दीना कॉलोनी, मल्लबाग श्रीनगर, फिरदौस अहमद भट पुत्र मोहम्मद अफज़ल भट निवासी अमदा कदल, लालबाज़ार, श्रीनगर और आफताब अहमद शाह पुत्र परवेज़ अहमद शाह निवासी ख्वाबबाज़ार, नवाहट्टा, श्रीनगर के रूप में हुई है।

उन्होंने कहा कि यह जांच एक शिकायत से जुड़ी है जिसमें आरोप लगाया गया था कि अर्शीद अहमद शोरा उर्फ बिलाल की अगुवाई में आरोपियों ने शिकायतकर्ता को 2.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की शॉल सप्लाई करने के लिए राजी किया। उन्होंने मुनाफ़े का वादा किया था लेकिन भुगतान नहीं किया। जांच के दौरान लगभग 68 लाख रुपये कीमत की 338 शॉल बरामद की गईं और कोर्ट के आदेश पर शिकायतकर्ता को सौंप दी गईं। जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच कश्मीर ने लोगों को आर्थिक धोखाधड़ी से सावधान रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना एसएसपी ईओडब्लू कश्मीर को देने की सलाह दी है।

जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद- रेलवे ने श्रीनगर-कटरा के बीच चलाई स्पेशल ट्रेन

श्रीनगर, 23 जुलाई । भारी बारिश, भूस्खलन और पत्थर गिरने की वजह से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बंद है। ऐसे में फंसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने गुरुवार को श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच एक स्पेशल ट्रेन शुरू की।

एक आधिकारिक सूचना के अनुसारयह स्पेशल ट्रेन जम्मू के कमर्शियल कंट्रोल के अनुरोध पर शुरू की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाबंदियों और ट्रैफिक की धीमी गति के कारण यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया। सूचना में कहा गया है कि यह ट्रेन शाम 5:00 बजे श्रीनगर से रवाना होगी और बनिहाल होते हुए रात 8:15 बजे कटरा पहुँचेगी।

24 जुलाई को वापसी की यात्रा में यह सुबह 8:45 बजे कटरा से रवाना होगी और सुबह 11:50 बजे श्रीनगर पहुँचेगी। इसमें बताया गया है कि स्पेशल ट्रेन बनिहाल और कटरा के बीच दोनों दिशाओं में बिना रुके चलेगी

और

इसे आठ-कोच वाली एमईएमयू रेक के साथ चलाया जाएगा। यह अतिरिक्त सेवा ऐसे समय में शुरू की गई है जब जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार दूसरे दिन भी बंद है। कई जगहों पर भूस्खलन, पत्थर गिरने और सड़क के धंसने के कारण सैकड़ों गाड़ियाँ और यात्री फँसे हुए हैं

छात्रों के विरोध और युवाओं के आक्रोश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, संवाद जरूरी: मुख्यमंत्री उमर

श्रीनगर, 23 जुलाई। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के विरोध को केंद्र सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि युवाओं के भीतर जो आक्रोश है, उसे संवाद के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए।

श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, किसी न किसी समय सरकार को इन युवाओं से बातचीत करनी ही होगी। इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब कॉकरोच जनता पार्टी ने पहली बार जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था, तब उसमें बहुत कम लोग शामिल हुए थे और कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था। लोग कह रहे थे कि उनके साथ कोई नहीं है, सोशल मीडिया पर लाखों समर्थक होने के बावजूद लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, अब दिल्ली की स्थिति सबके सामने है। आज नई दिल्ली का बड़ा हिस्सा बंद है। कल रात भी जंतर-मंतर के पास आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

पुलिसकर्मी की हत्या के अगले दिन आज अनंतनाग में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों के घर तोड़े गए

अनंतनाग, 23 जुलाई । गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में लश्कर-ए-तैयबा (एल ई टी) के दो आतंकवादियों के घर गिरा दिए गए।

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई बुधवार को अनंतनाग के लाल चौक पर हुई गोलीबारी की घटना में आतंकवादियों द्वारा एक पुलिसकर्मी की हत्या किए जाने के एक दिन बाद की गई।

उन्होंने बताया कि तोड़े गए घर बिजबेहरा के गुरी निवासी आदिल ठोकर और हसनपोरा निवासी हारून गनई के थे। अधिकारियों ने कहा कि यह तोड़फोड़ ज़िले में आतंकवादियों और उनके सपोर्ट नेटवर्क के ख़िलाफ़ चल रही कार्रवाई का हिस्सा थी।

मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर में जनसेवा बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित परियोजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश

श्रीनगर, 23 जुलाई। मुख्य सचिव अतल डुल्लू ने आज जम्मू-कश्मीर में सुशासन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की स्थापना की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में संबंधित प्रशासनिक सचिवों के अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जम्मू, बिसाग तथा केंद्र शासित प्रदेश के अन्य संबंधित अधिकारियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शासन व्यवस्था को दक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी और अधिक प्रभावी बनाने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि सरकार को उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग केवल डिजिटल उपकरणों के रूप में नहीं, बल्कि बेहतर प्रशासन, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाने के लिए एक रणनीतिक माध्यम के रूप में

करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि तकनीकी समाधान मौजूदा डिजिटल व्यवस्था के पूरक होने चाहिए, न कि समानांतर प्रणाली के रूप में विकसित किए जाएं। इससे सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और वर्तमान डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सहज समन्वय सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक विभागों से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित कर चिन्हित एआई परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन का आह्वान किया। उन्होंने विभागों को आवश्यकतानुसार समर्पित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा एआई समाधान विकसित करने, परीक्षण और सत्यापन के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़े समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आंकड़ों की गुणवत्ता, विभिन्न प्रणालियों के बीच समन्वय और विभागीय स्वामित्व सरकारी कार्यों में एआई के सफल उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।

सुनियोजित क्रियान्वयन ढांचे पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभागीय नोडल अधिकारियों, तकनीकी भागीदारों, विषय विशेषज्ञों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ क्षेत्रवार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। इन कार्यशालाओं में आंकड़ों की उपलब्धता, आधारभूत संरचना की तैयारी, कार्यप्रणाली तथा जमीनी स्तर की आवश्यकताओं का व्यापक आकलन किया जाए, ताकि पायलट परियोजनाओं के शुरू होने से पहले व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की जा सके और संभावित चुनौतियों की समय रहते पहचान हो सके।

भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जम्मू शहर में नगर निगम ने तैयारियों को किया तेज

जम्मू, 23 जुलाई। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा समय में बारिश काफी ज्यादा हो रही है। इसी के दौरान मौसम विभाग ने भी बारिशों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। इन बारिशों के कारण जम्मू-कश्मीर में काफी ज्यादा नुकसान और तबाही देखने को मिल रही है।

वहीं जम्मू शहर में भारी बारिश के बाद सुबह-सुबह ही जम्मू नगर निगम ने मॉनसून की तैयारियों को और तेज कर दिया है। इसके तहत नालियों की तेजी से सफाई और गाद निकालने का अभियान शुरू किया गया है साथ ही जल-जमाव और नालियां बंद होने की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए एक खास इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम भी सक्रिय किया गया है।

जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉ. देवांश यादव के निर्देशों पर अमल करते हुए सफाई टीमें शहर भर की बड़ी और छोटी नालियों की सफाई और गाद निकालने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं ताकि बारिश का पानी आसानी से बह सके और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ का ख़तरा कम हो सके। चल रहे कामों की प्रगति का जायजा लेने के लिए, संयुक्त आयुक्त (स्वास्थ्य और स्वच्छता) अब्दुल सत्तार ने जम्मू में कई जगहों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फील्ड अधिकारियों और सफाई टीमों को गाद निकालने (डीसिल्टिंग) का काम तेजी से करने, जल निकासी व्यवस्था को सुचारू रखने और लगातार बारिश के कारण पैदा होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए। मानसून के दौरान लोगों की सुरक्षा के प्रति जेएमसी द्वारा प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कमिश्नर डॉ. देवांश यादव ने सभी अधिकारियों को 24म7 सतर्क रहने और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मैनपावर और मशीनरी तैनात करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जलभराव या बंद नालियों से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई में देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम लोगों को तुरंत मदद देने के लिए जेएमसी ने नॉर्थ ज़ोन और साउथ ज़ोन दोनों के लिए मॉनसून इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की हैं। जिन नागरिकों को जल-जमाव, नालियों के ओवरफ्लो होने या नालों के जाम होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, खासकर रात के समय।

उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बहाली कार्यों की समीक्षा की, त्वरित राहत और दीर्घकालिक रोकथाम उपायों पर दिया जोर

राजौरी, 23 जुलाई। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने आज नौशेरा में हाल ही में आई अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के बाद चल रहे बहाली कार्यों और आपातकालीन राहत उपायों की समीक्षा के लिए एक व्यापक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने संबंधित सभी विभागों की तैयारियों और प्रतिक्रिया का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक सेवाओं की शीघ्र बहाली तथा प्रभावित लोगों को प्रभावी राहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने विभागवार बहाली कार्यों की समीक्षा करते हुए सड़कों, पेयजल आपूर्ति, बिजली तथा अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी विभागों को नुकसान का व्यापक आकलन शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए ताकि राहत और पुनर्बहाली के कार्य बिना किसी देरी के शुरू किए जा सकें।

दीर्घकालिक आपदा न्यूनीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए उपमुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं बाढ़

नियंत्रण विभाग को निर्देश दिया कि वह अगले पांच दिनों के भीतर एक विस्तृत योजना तैयार कर प्रस्तुत करे, जिसमें फ्लैश फ्लड के प्रभाव को कम करने तथा भविष्य में इस प्रकार की क्षति रोकने के लिए तत्काल और स्थायी उपाय सुझाए जाएं। उन्होंने वैज्ञानिक योजना, संवेदनशील क्षेत्रों को मजबूत बनाने तथा टिकाऊ बाढ़ प्रबंधन रणनीतियां अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने, बहाली कार्यों की लगातार निगरानी करने तथा सभी प्रभावित परिवारों तक समय पर सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हरसंभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

फ्लैश फ्लड के दौरान जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभागों द्वारा की गई त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई की सराहना करते हुए उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण तथा कठिन परिस्थितियों में किए गए बचाव, राहत और बहाली कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने सभी से इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य जारी रखने और प्रत्येक प्रभावित परिवार तक समय

जावेद राणा ने मेंढर में बाढ़ राहत एवं बहाली कार्यों की समीक्षा की

मेंढर, 23 जुलाई। जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज मेंढर में जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बहाली और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

अधिकारियों ने मंत्री को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान, आवश्यक सेवाओं की बहाली, राहत कार्यों तथा नुकसान के आकलन की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी।

मंत्री ने अधिकारियों को बहाली कार्यों में तेजी लाने, प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने तथा सामान्य स्थिति जल्द बहाल करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।

जावेद राणा ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों द्वारा प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त कर उनकी जांच की जाए, ताकि सभी वास्तविक मामलों में निर्धारित नियमों के अनुसार राहत, मुआवजा और पुनर्वास की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा सके।

प्रभावित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने उनसे नुकसान के सही आकलन में प्रशासन का पूरा सहयोग करने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार प्रत्येक पात्र मामले की संवेदनशीलता के साथ जांच करेगी और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी।

मंत्री ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को मनकोट नाले तथा अन्य प्रभावित स्थानों पर क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षा तटबंधों की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर ही विभाग को बाढ़ से प्रभावित सभी स्थलों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश भी दिए, जिसमें तत्काल राहत के लिए अस्थायी बहाली कार्यों के साथ-साथ भविष्य में बाढ़ से सुरक्षा के लिए स्थायी उपाय भी शामिल हों।

उन्होंने जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सभी आवश्यक सेवाओं की तत्काल बहाली सुनिश्चित करने तथा नुकसान के आकलन में तेजी लाकर प्रत्येक प्रभावित परिवार तक बिना किसी देरी के राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

राणा ने मेंढर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

मेंढर, 23 जुलाई। जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज पुंछ जिले के मेंढर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा कर हाल ही में हुई भारी वर्षा और फ्लैश फ्लड से हुए नुकसान का जायजा लिया तथा राहत, बहाली और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। दौरे के दौरान मंत्री के साथ उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) मेंढर इमरान कटारिया तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने छज्जला, मनकोट, डबराज, बलनोई, भाटीधार और सलवाह सहित कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मंत्री ने प्रभावित परिवारों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं, नुकसान और तत्काल आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि इस कठिन समय में सरकार पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है तथा राहत, पुनर्वास और सामान्य जीवन बहाल करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। जावेद राणा ने कहा, *हम सब इस कठिन समय में एक साथ हैं। हाल की बाढ़ ने पीर पंजाल क्षेत्र में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और निजी संपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और तब तक चैन से नहीं बैठेगी, जब तक सभी प्रभावितों तक राहत नहीं पहुंच जाती, क्षतिग्रस्त ढांचे की बहाली नहीं हो जाती और पूरे जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की बहाली और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सामान्य स्थिति जल्द बहाल करने तथा सार्वजनिक ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

एडीएचडी
ध्यान की कमी

लापरवाही, अस्थिरता, हर समय उछलकूद और आवेग बच्चों में होना सामान्य बात है। लेकिन यदि बच्चा अधिकतर समय ऐसा ही रहता है तो यह एडीएचडी का असर भी हो सकता है। अनुमान के अनुसार भारत में प्रत्येक 20 में से 1 बच्चे में एडीएचडी के लक्षण देखने को मिलते हैं। चूंकि लक्षण सामान्य हैं, ऐसे में समय पर जांच व उपचार की कमी समस्या को बढ़ा देती है, बता रहे हैं

बच्चों में एडीएचडी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। मानसिक व व्यवहार संबंधी समस्याओं के प्रति बढ़ती जानकारी का ही प्रभाव है कि माता-पिता अब बच्चों की समस्याओं को गंभीरता से ले रहे हैं। बावजूद बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो नहीं जानते कि उनके बच्चे या फिर वे खुद एडीएचडी के शिकार हैं। एडीएचडी यानी एटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसॉर्डर। यूं बच्चों में लापरवाही, असावधानी, अति सक्रियता व आवेग का होना सामान्य है, लेकिन इन लक्षणों वाला हर बच्चा एडीएचडी का शिकार हो, यह जरूरी भी नहीं। इतना अवश्य है कि एडीएचडी से पीड़ित बच्चों में यह व्यवहार व विकास संबंधी डिसॉर्डर अधिक गंभीर और लंबे समय तक देखने को मिलता है। यही वजह है कि इसकी जांच के लिए बच्चे के व्यवहार का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है।

बच्चों में यह समस्या अकसर 3-4 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। 12 वर्ष से छोटे बच्चों में कभी भी इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं। एडीएचडी बच्चों में पाया जाने वाला मस्तिष्क संबंधी डिसॉर्डर है, जिसके कारण वे अपने व्यवहार और आवेग पर काबू नहीं रख पाते हैं। एसोचैम के अनुसार वर्ष 2005 में इसके मामले 4ब्न थे, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 11ब्न हो गये हैं। इन वर्षों में एडीएचडी से प्रभावित बच्चों की संख्या में 175ब्न तक की वृद्धि देखने को मिली है। एक अनुमान के अनुसार बड़े शहरों में 20 में से 1 बच्चा एडीएचडी से पीड़ित है। दुनियाभर में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के इससे प्रभावित होने के मामले अधिक होते हैं।

एडीएचडी के कारण

एडीएचडी क्यों होता है, इसके निश्चित कारणों के बारे में नहीं पता, पर कुछ संभावित कारण इस प्रकार हैं...

आनुवंशिकता: कुछ परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में ऐसे जींस का ट्रांसफर होता है, जिससे मस्तिष्क के उन हिस्सों के ऊतक पतले हो जाते हैं, जो ध्यान से संबंधित होते हैं। कई बार समय के साथ ये ऊतक सामान्य हो जाते हैं, जिससे स्थिति में सुधार आता है।

पर्यावरणीय कारक: गर्भावस्था में सिगरेट व शराब का सेवन करने वाली महिलाओं के बच्चों में एडीएचडी की आशंका अधिक होती है। छोटी उम्र में लगातार लेड की उच्च मात्रा के संपर्क में रहने से भी ये हो सकता है।

लक्षण और संकेत

एडीएचडी डिसॉर्डर में तीन लक्षण सबसे प्रमुख हैं- लापरवाही, अतिसक्रियता और आवेग। कुछ बच्चों में ये तीनों लक्षण होते हैं, तो कुछ बच्चों में अनमनापन व सावधानी की कमी होती है, पर वे अतिसक्रिय नहीं होते। कुछ अतिसक्रिय और आवेगी होते हैं, पर लापरवाह नहीं। कुछ में दोनों तरह के लक्षण होते हैं।

इनअटेंटिव बच्चों के लक्षण इस प्रकार हैं...
- आसानी से ध्यान भटकना, एक काम करते-करते दूसरा शुरू कर देना, एकाग्र नहीं हो पाना। रोजमर्रा के कामों को भूलना। कार्य को व्यवस्थित ढंग से न कर पाना।
- मनपसंद काम करते हुए भी कुछ मिनटों में बोर होना।
- होमवर्क व अन्य कार्यों को समय पर पूरा न कर पाना। अपने खिलौने, कॉपी, पेन, पैंसिल, रबर आदि खो देना।
- बात को ध्यान से न सुनना, अधिक दिमागी काम को देर तक न कर पाना।

अतिसक्रिय यानी हाइपरएक्टिव बच्चों के लक्षण हैं-
- अपनी सीट पर लगातार हिलना-डुलना।
- बिना रुके लगातार व अधिक बोलना।
- खाना खाते समय या स्कूल में बिना हिले-डुले बैठने में समस्या होना। लगातार यहां-वहां घूमना।

अधिक आवेग में रहने वाले बच्चों के प्रमुख लक्षण हैं
- बहुत अधीर होना। प्रश्न से पहले उत्तर बोलना। दूसरों की बातचीत को बीच में रोकना।
- अपनी भावनाएं खुलकर अभिव्यक्त करना।
- बिना सोचे-समझे कोई काम करना।
- खेल में अपनी बारी की प्रतीक्षा करने में समस्या होना।

चीनी और फूड एडिटिव : कई विशेषज्ञ हाइपरएक्टिविटी को अधिक मात्रा में रिफाइंड शुगर व फूड एडिटिव का सेवन करने से जोड़ते हैं। हालांकि इस संबंध में मतभेद भी हैं और शोध कार्य चल रहे हैं।

रासायनिक असंतुलन: मस्तिष्क के रसायनों में असंतुलन होने पर भी एडीएचडी के लक्षण उभरते हैं। मस्तिष्क में अटेंशन को नियंत्रित करने वाला हिस्सा एडीएचडी से पीड़ित बच्चों में कम सक्रिय होता है।

मस्तिष्क का चोटिल होना: कई बार चोट के कारण मस्तिष्क का अग्रभाग, जिसे फंटल लोब कहते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे आवेगों और भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या आती है।

समय पूर्व जन्म होना: समय पूर्व जन्म लेने वाले बच्चे या जन्म के समय बेहद कम वजनी बच्चों में भी इसकी आशंका अधिक होती है।

वयस्क भी हो सकते हैं शिकार

कुछ बच्चों में बड़े होने पर भी एडीएचडी की समस्या बनी रहती है। कई वयस्क ये जानते भी नहीं कि वे इससे प्रभावित हैं। एडीएचडी से पीड़ित वयस्कों में सुबह उठना, काम के लिये घर से निकलना, समय पर ऑफिस पहुंचना और अपने रोजमर्रा के कार्यों को बेहतर व समय पर पूरा करना एक चुनौतीभरा कार्य होता है। इन वयस्कों का स्कूल में फेल होने का इतिहास होता है। ये अकसर संबंध ढंग से नहीं निभा पाते। बेचैनी के शिकार रहते हैं। बचपन में सही उपचार नहीं मिलने के कारण कुछ लोगों में अपने व्यवहार के लिए नकारात्मक भावनाएं भी घर कर लेती हैं। यही वजह है कि सही समय पर एडीएचडी की पहचान होने पर व्यक्ति को समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलती है।

उपचार

इसका कोई स्थायी उपचार नहीं है। पीड़ित बच्चे को उसके व्यवहार पर काबू रखने का अभ्यास कराया जाता है, ताकि वह सामान्य जीवन जी सके। स्टीम्युलेंट मेडिकेशन के अलावा ये थेरेपी भी कारगर पायी गयी हैं-

साइकोथेरेपी (काउंसलिंग): इससे पीड़ित बच्चों को अपनी भावनाओं और हताशाओं को बेहतर ढंग से संभालना सिखाया जाता है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास भी किया जाता है। परिवार के सदस्यों को भी काउंसलिंग दी जाती है।

बिहेवियरल थेरेपी: बच्चे के व्यवहार में सुधार लाया जाता है। पीड़ित बच्चे को स्कूल का होमवर्क या दूसरे प्रेक्टिकल कार्यों के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाती है। बच्चे को स्वयं पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। गुस्से को काबू रखना या कार्य को सोच-समझकर करना सिखाया जाता है। अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, दूसरों की सहायता करना व उनसे सहायता मांगना, दूसरों के तंग करने पर सही प्रतिक्रिया देना आदि सिखाते हैं।

डांस थेरेपी: दूसरे बच्चों के साथ घुलने-मिलने के अलावा डांस से बच्चों का शरीर पर नियंत्रण बढ़ता है।

प्ले थेरेपी: इसमें पीड़ित बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। काउंसलर माता-पिता को बच्चे को आउटडोर व इनडोर गेम्स खेलने देने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे बच्चों की सेहत व नींद प्रक्रिया में सुधार आता है।

माता-पिता की भूमिका

यह समझना जरूरी है कि एडीएचडी के कारण मस्तिष्क में रसायनों का असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण बच्चा अपने आवेगों और व्यवहार पर काबू नहीं रख पाता। वह जानकर ऐसा नहीं कर रहा होता। माता-पिता के लिए बच्चे को प्रेम और सकारात्मक भावनाओं के साथ संभालना जरूरी है।
- बच्चे की दिनचर्या निर्धारित करें और उसका पालन करने के लिए प्रेरित करें।
- अच्छा काम करने पर प्रशंसा करें।
- टीवी व मोबाइल स्क्रीन के सामने अधिक देर न बैठने दें। आउडडोर खेल खेलने के लिये प्रेरित करें।
- बच्चों के खान-पान पर ध्यान दें। ऐसी चीजें, जिन्हें खाने पर वे हाइपरएक्टिव होते हैं, उन्हें न दें।
- बच्चे पर स्कूल में अच्छे प्रदर्शन के लिए दबाव न बनाएं। तनाव की अधिकता से यह समस्या बढ़ती है।
- स्कूल व प्रशासन से बच्चे के बारे में खुलकर बात करें। उनसे अनुरोध करें कि वे बच्चे को प्रथम पंक्ति में बिठाएं। खिड़की के पास न बिठाएं। सबके सामने न डांटकर अलग से समझाएं।

(हमारे विशेषज्ञ : डॉ. शंभवी सेठ, कंसल्टेंट, पीडियाट्रिक डेवलपमेंट, बीएलके सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल, नई दिल्ली, डॉ. संदीप गोविल, मनोचिकित्सक, अटलांटा हॉस्पिटल)

मासिक चक्र (पीरियड्स) के दौरान होने वाले रक्तस्राव और दर्द भरे शारीरिक संपर्क को गंभीरता से लें। स्थितियों के अधिक गंभीर होने से पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें। इस रोग के उपचार के लिए दवाएं और सर्जरी का उपयोग किया जाता है

एंडोमीट्रियोसिस
अब नहीं रहा अभिशाप

संतानहीनता के प्रमुख कारणों में एक कारण एंडोमीट्रियोसिस नामक रोग है, जिसका अब कारगर इलाज संभव है। एंडोमीट्रियोसिस गर्भाशय से जुड़ी एक समस्या है। यह समस्या महिलाओं की प्रजनन क्षमता को सर्वाधिक प्रभावित करती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि गर्भधारण करने और बच्चे को जन्म देने में गर्भाशय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या है रोग का स्वरूपः गर्भाशय की अंदरूनी परत की कोशिकाओं के असामान्य विकास को एंडोमीट्रियोसिस नामक रोग कहा जाता है। यह समस्या तब होती है, जब कोशिकाएं गर्भाशय के बाहर विकसित हो जाती हैं, जिसे एंडोमीट्रियोसिस इंप्लांट कहते हैं। ये इम्प्लांट्स सामान्यतः अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब्स, गर्भाशय की बाहरी सतह पर, आंत व पेल्विक गुहा की सतह पर पाए जाते हैं। ये वेंजाइना, सरविक्स और यूरीनरी ब्लैडर पर भी पाये जा सकते हैं, लेकिन पेल्विस के दूसरे स्थानों की बजाय यहां सामान्यता कम पाए जाते हैं।

कारण : एंडोमीट्रियोसिस महिलाओं को उनके प्रजनन काल के दौरान प्रभावित करता है। एंडोमेट्रियोसिस के अधिकतर मामले 25-35 वर्ष की महिलाओं में देखे जाते हैं।

लक्षण : अधिकतर महिलाओं में एंडोमीट्रियोसिस के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें मासिक चक्र (पीरियड्स) के समय अत्यधिक दर्द होता है। इस दर्द की तीव्रता हर महीने बदल सकती है और अलग-अलग महिलाओं में अलग-अलग हो सकती है।

पेल्विक पेन (पेट के निचले भाग में दर्द) : यह दर्द कई दिनों तक जारी रह सकता है। इससे कमर में दर्द ओर पेट में दर्द भी हो सकता है। यह पीरियड्स शुरू होने से पहले हो सकता है और कई दिनों तक चल सकता है।

इलाज : मासिक चक्र (पीरियड्स) के दौरान होने वाले रक्तस्राव और दर्द भरे शारीरिक संपर्क को गंभीरता से लें। स्थितियों के अधिक गंभीर होने से पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें। इस रोग के उपचार के लिए दवाएं और सर्जरी का उपयोग किया जाता है। हार्मोन थेरेपी भी इस रोग के उपचार के लिये की जाती है, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान होने वाले हार्मोन परिवर्तन के कारण भी यह समस्या हो जाती है। हार्मोन थेरेपी एंडोमीट्रियोसिस की वृद्धि को धीमा करती है। एंडोमेट्रियोसिस के कारण होने वाली संतानहीनता की समस्या के लिये डॉक्टर सर्जिकल उपचार को सबसे बेहतर मानते हैं।

संतानहीनता से संबंध : जो महिलाएं एंडोमीट्रियोसिस से ग्रस्त हैं, उनमें से 35-50 प्रतिशत महिलाओं को गर्भधारण करने में समस्या होती है। इसके कारण फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती हैं। इस कारण अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाता। कभी-कभी अंडाणु या शुक्राणु को भी नुकसान पहुंचता है। इससे भी गर्भधारण नहीं हो पाता। जिन महिलाओं में यह समस्या गंभीर नहीं होती उन्हें गर्भधारण करने में अधिक समस्या नहीं होती।

- डॉ. शीतल अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अपोलो नोवा हॉस्पिटल

जान लेवा घबराहट
एंग्जाइटी डिसऑर्डर

एंग्जाइटी डिसऑर्डर घबराहट की बीमारी है, जिसे ''पैनिक अटैक डिसऑर्डर' भी कहते हैं। आज देश में लगभग दो से चार प्रतिशत लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। यह बीमारी आमतौर पर युवा लोगों, खासकर युवतियों को अधिक होती है। वैसे, यह बीमारी किसी भी आयु में हो सकती है, लेकिन पन्द्रह सें पैंतालीस साल की उम्र में अधिक होती है। जब यह बीमारी चालीस या उसके बाद की उम्र में होती है तब ई.सी.जी., एंजीयोग्राफी एवं ट्रेड मिल टेस्ट आदि परीक्षण सामान्य आने पर इसे ''कार्डियक न्यूरोसिस' या ''इस्कीमिया' मान लिया जाता है। लेकिन वास्तव में यह ''एंग्जाइटी डिसऑर्डर' है

एंग्जाइटी डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण घबराहट है। इस बीमारी के तहत मांसपेशियों और पूरे शरीर में सख्ती आने लगती है। रक्त का संचरण, हृदय की धड़कन, रक्तचाप, सांसें और उपापचय-दर बढ़ जाती है तथा पसीना अधिक आने लगता है।

वैसे, घबराहट हर जीव के प्रतिरक्षा-तंत्र का अभिन्न हिस्सा है और यह उसके जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। खतरे की आशंका से ही घबराहट होती है। जब हमें खतरे का अहसास होता है या खतरे का संकेत मिलता है तो हमारा शरीर उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार होने लगता है। खतरे दो प्रकार के होते हैं- काल्पनिक एवं यथार्थ। जब खतरा वास्तव में उत्पन्न हो जाए एवं खतरे का आभास मिले तब घबराहट होना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब व्यक्ति बचपन या किशोरावस्था से ही तनावपूर्ण जीवन जी रहा होता है तो उसमें एंग्जाइटी जीवन-शैली का हिस्सा बन जाती है। व्यक्ति को जिस परिस्थिति में पैनिक अटैक होता है, अगर बाद में उसी परिस्थिति से वह गुजरे, तब उसे दोबारा पैनिक अटैक होगा। जैसे अगर गाड़ी चलाते समय पैनिक अटैक हो जाए तो उसे दोबारा गाड़ी चलाते समय यह अटैक होने का खतरा रहता हैं रोगी खुद भी ऐसी परिस्थिति में पड़ने से अभी जान निकल जाएगी। एंग्जाइटी डिसऑर्डर का मुख्य कारण तनाव एवं भय है। पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट, घर-दफ्तर की समस्याएं, पढ़ाई-करियर संबंधी समस्याएं आदि तनाव के कारण हैं। ये समस्याएं हर व्यक्ति में तनाव पैदा करती हैं। लेकिन जब व्यक्ति बचपन या किशोरावस्था से ही तनावपूर्ण जीवन जी रहा होता है तो उसमें एंग्जाइटी जीवन-शैली का हिस्सा बन जाती है। व्यक्ति को जिस परिस्थिति में पैनिक अटैक होता है, अगर बाद में उसी परिस्थिति से वह गुजरे, तब उसे दोबारा पैनिक अटैक होगा। जैसे अगर गाड़ी चलाते समय पैनिक अटैक हो जाए तो उसे दोबारा गाड़ी चलाते समय यह अटैक होने का खतरा रहता हैं रोगी खुद भी ऐसी परिस्थिति में पड़ने से व्यक्ति को भीड़-भाड़ वाले बाजार, सड़क, बस-रेलगाड़ी या हवाई सफर में पहला अटैक होता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति को अकेले में सफर नहीं करना चाहिए। दरअसल एंग्जाइटी डिसऑर्डर सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक कारणों से पैदा होती है। इसलिए इसके उपचार एवं बचाव के तरीके भी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक होंगे। दवाइयां भी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तौर पर असर करेंगी। पैनिक अटैक के इलाज के लिए अलप्रेजालोन, डुराजोपाम, डायजिपाम जैसी बेंजोडाइजापिन ग्रुप की दवाइयां दी जाती हैं। इस ग्रुप की दवाइयों की विशेषता यह है कि ये घबराहट कम करती हैं, मांसपेशियों को ढीला करती हैं और अच्छी नींद लाती हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के इलाज के लिए इन दवाइयों के अलावा बिहेवियर थेरेपी भी कारगर होती है। विहेवियर थेरेपी के तहत रोगी को रिलैक्सेशन की विशेष तकनीकें सिखाई जाती हैं। इसके लिए योग का भी सहारा लिया जाता है। इस तकनीकों की मदद से रोगी अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करता है तथा अपनी सोच एवं व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ताकि वह दवाइयों के बगैर भी पैनिक अटैक से मुक्त हो जाए।

वैसे, घबराहट हर जीव के प्रतिरक्षा-तंत्र का अभिन्न हिस्सा है और यह उसके जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। खतरे की आशंका से ही घबराहट होती है। जब हमें खतरे का अहसास होता है। या खतरे का संकेत मिलता है तो हमारा शरीर उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार होने लगता है।

इसे ''पैनिक अटैक' नहीं कहा जाएगा, बल्कि यह ''जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर' है। लेकिन कई बार व्यक्ति को खतरे का अहसास यों ही होता रहता है, ऐसी स्थिति में स्नायु-पणाली शरीर में वही परिवर्तन पैदा कर देती हैं, जो परिवर्तन वास्तविक खतरे के समय पैदा होते हैं और यही स्थिति ''एंग्जाइटी डिसऑर्डर' कहलाती है। जिस व्यक्ति को एंग्जाइटी का दौरा पड़ता है, उसे लगता है कि बचता है। यह फोबिया है, सबसे सामान्य फोबिया ''क्लास्ट्रोफोबिया' है। इसमें व्यक्ति को भीड़-भाड़ वाली या तंग जगह में घबराहट होती है। इससे ग्रस्त

- आभा

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

संयुक्त कृषि निदेशक (इनपुट) ने रबी सीजन के लिए बीज की मांग और उपलब्धता की समीक्षा की

जम्मू, 23 जुलाई। संयुक्त कृषि निदेशक (इनपुट) जम्मू संजय आनंद ने आज कृषि भवन, तालाब तिल्लो में रबी 2027-28 के लिए सभी कृषि फसलों के ब्रीडर बीज की मांग को अंतिम रूप देने तथा रबी 2026-27 के लिए ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित बीज की उपलब्धता की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में प्रमुख कृषि फसलों के लिए ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित बीज की आवश्यकता एवं उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की गई, ताकि आगामी रबी सीजन में किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जा सके। फसलवार बीज मांग, उत्पादन लक्ष्य तथा कृषि विभाग और शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (स्कुआस्ट-जम्मू) के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रभावी बीज योजना और वितरण पर भी चर्चा की गई। संयुक्त कृषि निदेशक ने ब्रीडर बीज की मांग को समय पर अंतिम रूप देने पर जोर देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीज की पर्याप्त मात्रा बुवाई से पहले ही विभागीय फार्मों तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर बीज योजना से फसल उत्पादकता बढ़ाने, किस्मों की शुद्धता बनाए रखने तथा बीज उत्पादन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में सहायता मिलेगी। बैठक में संयुक्त कृषि निदेशक (फार्म/एसएलयूबी) अमन ज्योति शर्मा, पौधा प्रजनन विभाग की विभागाध्यक्ष, स्कुआस्ट-जम्मू डॉ. तुहिना डे, नोडल अधिकारी (बीज) स्कुआस्ट-जम्मू डॉ. विजय भारती, आलू विकास अधिकारी जम्मू रवि शर्मा, संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी जम्मू निर्मल प्रकाश शर्मा, सहायक वनस्पति वैज्ञानिक अजीत सिंह तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

डीसी उधमपुर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की

उधमपुर, 23 जुलाई। उपायुक्त उधमपुर मिंगा शेरपा ने आज जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला अधिकारियों की बैठक की।

बैठक में बताया गया कि मुख्य समारोह राजकीय स्नातकोत्तर डिग्री कॉलेज (बालक) में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बैठने की व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, प्राथमिक उपचार, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली तथा परिवहन व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई।

कश्मीर घूमने आए यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन का संचालन

जम्मू, 23 जुलाई। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात धीमा होने से कश्मीर घाटी में फंसे यात्रियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे, जम्मू मंडल द्वारा आज दिनांक 23 जूलाई को श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक एक विशेष ट्रेन का संचालन किया गया।

यह निर्णय वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, श्री उचित सिंघल के निर्देश पर यात्रियों की सुविधा एवं आरामदायक आवागमन सुनिश्चित करने के लिए तुरंत प्रभाव से लिया गया है।

इस विशेष ट्रेन ने आज दिनांक 23 जुलाई 2026 को शाम 17.10 बजे श्रीनगर रेलवे स्टेशन से प्रस्थान किया। मार्ग में यह ट्रेन बनिहाल रेलवे स्टेशन पर ठहराव करते हुए रात्रि 20:15 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। विशेष ट्रेन की सुविधा का लाभ लगभग 600 से अधिक यात्रियों ने उठाया।

इस विशेष ट्रेन के संचालन से कश्मीर घाटी में फंसे यात्रियों को सुरक्षित एवं त्वरित यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहायता मिलेगी, विशेषकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा और जम्मूतवी से आगे की ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को। इससे पूर्व भी जम्मू मंडल द्वारा यात्रियों को बेहतर एवं आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाता रहा है।

इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, जम्मू श्री उचित सिंघल ने कहा कि,

द्वफ्रयात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़क यातायात धीमा होने तथा यात्रियों को समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मंडल प्रशासन द्वारा त्वरित निर्णय लेकर यह विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, ताकि किसी भी यात्री को असुविधा न हो। हम सभी यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि यात्रा से पूर्व NTES ऐप, IRCTC वेबसाइट अथवा 139 हेल्पलाइन के माध्यम से ट्रेन की अद्यतन स्थिति अवश्य जांच लें।

यात्रियों की सेवा में तत्पर रहना जम्मू मंडल की निरंतर प्रतिबद्धता है।

गाड़ी की टक्कर से महिला की मौत

श्रीनगर, 23 जुलाई (हि.स.)। गुरुवार को श्रीनगर के बेमिना इलाके में जेवीसी अस्पताल के पास एक अज्ञात गाड़ी की टक्कर से 59 वर्षीय महिला की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह हादसा जेवीसी अस्पताल के पास हुआ जहाँ एक अज्ञात गाड़ी ने महिला को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि उन्हें गंभीर हालत में जेवीसी अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला की पहचान बाद में जमीला बानो (59) के रूप में हुई, जो बडगाम के कनिह गुंड की रहने वाली थीं और अली मोहम्मद राथर की पत्नी थीं।

छात्रों के समर्थन में गरजे अमरीश जसरोटिया-कहा आवाज दबाना लोकतंत्र पर हमला, न्याय तक संघर्ष जारी रहेगा

कठुआ, 23 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में कठुआ के युवा नेता अमरीश जसरोटिया ने जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जसरोटिया ने अपने संबोधन में कहा कि देश के युवाओं और छात्रों के मुद्दों को नजरअंदाज करना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की जायज मांगों को सुनने के बजाय दमनात्मक रवैया अपना रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। जसरोटिया ने युवाओं से एकजुट रहने और अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने का आह्वान किया।

जम्मू इलाके के कुछ हिस्सों में बारिश का एक नया दौर शुरू

जम्मू, 23 जुलाई (हि.स.)। मौसम विभाग द्वारा सुबह आठ बजे जारी ताजा जानकारी के अनुसार जम्मू इलाके के कुछ हिस्सों में बारिश का एक नया दौर शुरू हुआ है।

उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ते हुए इसके अगले कुछ घंटों में मुख्य रूप से सांबा, कठुआ, उधमपुर और चिनाब घाटी ज़िलों को प्रभावित करने की उम्मीद है। जैसे-जैसे यह सिस्टम आगे बढ़ेगा, यह दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी फैल सकता है जहाँ मौसम की अनुकूल स्थितियों के कारण बारिश और तेज़ हो सकती है। इस दौर के गुज़रने के बाद, कल जम्मू-कश्मीर में बारिश का एक और दौर आने की उम्मीद है।

भूस्खलन और भारी बारिश के कारण जम्मू-श्रीनगर एनएच-44 और डोडा-किश्तवाड़ रोड बंद

श्रीनगर, 23 जुलाई (हि.स.)। गुरुवार को भारी बारिश के कारण कई संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन, पत्थर और मालवा गिरने की घटनाओं के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (एनएच -44) पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है जिससे इस अहम रास्ते पर यातायात बाधित हुआ है।

अधिकारियों के अनुसार लगातार बारिश और भूस्खलन व मलबे के जमा होने से सड़क की हालत असुरक्षित हो गई है जिसके चलते डोडा-किश्तवाड़ रोड भी बंद कर दी गई है।

वहीं श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी (एसएसजी) रोड और ऐतिहासिक मुगल रोड ट्रैफिक के लिए खुले हैं हालांकि अधिकारियों ने यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि पूरे जम्मू-कश्मीर में मौसम खराब बना हुआ है। यातायात पुलिस ने कहा कि भारी बारिश केंद्र शासित प्रदेश के कई हाईवे और सड़कों को प्रभावित कर रही है जिससे भूस्खलन, पत्थर गिरने और सड़क जाम होने का खतरा बढ़ गया है।

अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे तब तक गैर-ज़रूरी यात्रा से बचें जब तक मौसम ठीक न हो जाए और सड़कों को गाड़ियों की आवाजाही के लिए सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए।

ट्रैफ़िक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले वे आधिकारिक ट्रैफ़िक कंट्रोल यूनिट्स और विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए सड़क की ताज़ा स्थिति की जाँच कर लें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल अभियन्ता-तृतीय/फिरोजपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित ई-निविदाएं, अंतिम तिथि **13.08.2026** समय **15:00 बजे** तक **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता अपने मूल/संशोधित निविदा बंद होने की तिथि तथा समय तक प्रस्तुत कर सकते हैं। मैन्युअल निविदा मान्य नहीं है और ऐसे किसी भी मैन्युअल प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार निविदा प्रपत्र की लागत और बयाना राशि का भुगतान केवल **www.ireps.gov.in** पोर्टल पर उपलब्ध ऑन लाइन साधनों के माध्यम जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, व क्रेडिट कार्ड आदि से भुगतान कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, एफ.डी.आर. व रसीदों आदि के माध्यम से भुगतान की अनुमति नहीं है।

निविदा प्रकार	निविदा अनुभाग	बोली प्रणाली
खुला	कार्य	एकल बोली प्रणाली
निविदा अपलोड करने की तिथि	**बोली शुरू की तिथि**	**बोली समापन की तिथि, समय**
21.07.2026	30.07.2026	13.08.2026, 15:00 बजे

क्रम संख्या	निविदा संख्या	निविदा का विवरण			
1.	68-2026-27-ADEN-I-ASR	सहायक मंडल अभियंता-प्रथम/अमृतसर के तहत अमृतसर में 60 बिस्तरों वाले पुरुष बैरक कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था।			
		विज्ञापन मूल्य (रु.)	ब्याना राशि	ऑफर की वैधता	समापन की अवधि
		3,35,16,328.56	6,70,300.00	60 दिन	06 महीने
		समान प्रकृति का कार्यः "इमारत/आवास का निर्माण।"			
2.	69-2026-27-ADEN-I-ASR	सहायक मंडल अभियंता-प्रथम/अमृतसर के अंतर्गत आने वाले सेक्शन में अटारी में 15 बिस्तरों वाली पुरुष बैरक की व्यवस्था।			
		विज्ञापन मूल्य (रु.)	ब्याना राशि	ऑफर की वैधता	समापन की अवधि
		84,50,589.30	1,69,000.00	60 दिन	12 महीने
		समान प्रकृति का कार्यः "इमारत/आवास का निर्माण।"			

नोटः 1. निविदा डालने से पहले, निविदाकर्ता निविदा के संबंध में जारी किए गए किसी भी शुद्धिपत्र की जाँच करेंगे। 2. हिन्दी में किसी भी त्रुटि हेतु अंग्रेजी वर्जन का अवलोकन करें, तथा अंग्रेजी वर्जन ही मान्य होंगे।

सं.: 68 & 69-2026-27-ADEN-I-ASR दिनांकः 23.07.2026 2542/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

करोड़ों के क्रिप्टो निवेश घोटाले में कोर्ट सख्त, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

कठुआ, 23 जुलाई (हि.स.)। कठुआ और देश के विभिन्न हिस्सों में सामने आए 2000 से 3000 करोड़ के क्रिप्टो निवेश घोटाले को लेकर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कठुआ ने 22 जुलाई 2026 को पारित अपने आदेश में अपराध शाखा को मामले में एफआईआर दर्ज करने और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान कई लोगों ने क्रिप्टो निवेश के नाम पर ठगी का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज करवाई थीं। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस, संबंधित अधिकारियों और यहां तक कि एसएसपी कार्यालय में भी अपनी शिकायतें दीं लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब मामले में जांच एजेंसियों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस आदेश के बाद पीड़ितों में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है वहीं संबंधित एजेंसियों के लिए मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है।

उत्तर रेलवे

ई. निविदा सूचना

वरिष्ठ मण्डल संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर, उत्तर रेलवे, फिरोज़पुर भारत के राष्ट्रपति की ओर से टैंडर नं0 433-सिग-टी-24-26-27 ई. टैंडरिंग के माध्यम से दिनांक **14.08.2026** को 15:00 बजे तक **https://www.ireps.gov.in** वेबसाईट पर निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता अपनी निविदाएं असली/संशोधित निश्चित किए गए समय तथा तारीख तक अवश्य जमा करवाएं। इस टैंडर के अर्न्तगत मैनुअल निविदा वर्जित है और अगर कोई मैनुअल निविदा प्राप्त होगी तो वह मान्य नहीं होगी। ठेकेदारों द्वारा टैंडर डाक्यूमैंट की कीमत और ब्याना राशि जोकि इस टैंडर के लिए मान्य है वह केवल आईआरईपीएस पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जैसेकि नैट बैंकिंग, डैबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि द्वारा ही स्वीकृत की जाएगी इसके अतिरिक्त डिमान्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपोजिट रसीद, एफडीआर इत्यादि के माध्यम द्वारा जमा करवाई गई राशि मान्य नहीं होगी।

एन। आई। टीः

कार्य का नाम	(i) फिरोजपुर डिवीजन में मौजूदा डेटा लॉगर्स की क्षमता को बदलना/अपग्रेड करना और डेटा लॉगर नेटवर्किंग मैनेजमेंट रूम की व्यवस्था करने का कार्य। (ii) फिरोजपुर डिवीजन में गुड्स शेड पर 550 CCTV कैमरे लगाने की व्यवस्था करने का कार्य। (iii) फिरोजपुर डिवीजन के 04 स्टेशनों (खोजेवाला, हुसैनपुर, पजियन और सुल्तानपुर लोधी) पर हिताची मेक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए तीन साल का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध का कार्य।		
टैंडर बन्द करने की तिथि तथा समय	(i) 14/08/2026 15:00 (ii) 14/08/2026 15:00 (iii) 14/08/2026 15:00	**टैंडर की अपलोड करने की तिथि तथा समय**	22.07.2026 17:27
अनुमानित कीमत	(i) 29545987.32 (ii) 23377399.98 (iii) 10449555.84	**बिडिंग आरम्भ की तिथि (आई.आर.ई.पी.एस.)**	(i) 31/07/2026 (ii) 31/07/2026 (iii) 31/07/2026
ब्याना राशि (रू)	(i) 590900.00 (ii) 467600.00 (iii) 209000.00	**कार्य पूरा करने की अवधी**	(i) 9 महीने (ii) 9 महीने (iii) 36 महीने
नोट	निविदाकर्ता नियमित रूप से वेबसाइट के संपर्क में रहकर निविदा संशोधनों, शुद्धिपत्र आदि के बारे में स्वयं को अपडेट रखें।		

निविदा सूचना सं0 :- **433-सिग-टी-24-26-27** दिनाँक- **22.07.2026** बंद होने की तिथि/समयः को **14.08.2026 15:00** बजे **2527/2026**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

निविदा संख्याः- 65, 67-2026-27-ADEN-2-FZR & 66-2026-27-ADEN-1-FZR दिनांक : 23.07.2026

मण्डल अभियंता- मुख्यालय, फिरोजपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित ई-निविदाएं, अंतिम तिथि 13.08.2026 समय 15:00 बजे तक **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता अपने मूल / संशोधित निविदा बंद होने की तिथि तथा समय तक प्रस्तुत कर सकते है। मैन्युअल निविदा मान्य नहीं है और ऐसे किसी भी मैन्युअल प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार निविदा प्रपत्र की लागत और बयाना राशि का भुगतान केवल **www.ireps.gov.in** पोर्टल पर उपलब्ध ऑन लाइन साधनों के माध्यम जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, व क्रेडिट कार्ड आदि से भुगतान कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, एफ.डी.आर. व रसीदों आदि के माध्यम से भुगतान की अनुमति नहीं है।

निविदा प्रकार	निविदा अनुभाग	पैकेट प्रणाली
खुला	कार्य	एकल पैकेट प्रणाली
निविदा अपलोड करने की तिथि	बोली शुरू की तिथि	निविदा समापन की तिथि तथा समय
21.07.2026	30.07.2026	13.08.2026 15:00 बजे

क्र.	निविदा संख्या	निविदा का विवरण			
1	65-2026-27-ADEN-2-FZR	सहायक मंडल अभियंता-द्वितीय/फिरोजपुर के अंतर्गत फाजिल्का, जलालाबाद और फिरोजपुर शहर में स्टाफ क्वार्टरों की आर्च रूफ की मरम्मत/बदलाव।			
		विज्ञापन मूल्य (रु.)	ब्याना राशि	ऑफर की वैधता	समापन की अवधि
		7996458.77	159900.00	60 दिन	12 महीने
		सामान प्रकृति का कार्यः "ट्रैक के काम के अलावा कोई भी सिविल काम।"			
2	66-2026-27-ADEN-1-FZR	सहायक मंडल अभियंता-प्रथम/फिरोजपुर के तहत 25 स्टेशनों और मंडल अभियंता-मुख्यालय/फिरोजपुर के तहत 55 स्टेशनों पर टैक्टाइल पाथ, पार्किंग एरिया, दिव्यांगजन टॉयलेट, COP आदि जैसी MEA और दिव्यांगजन सुविधाएं उपलब्ध कराना।			
		विज्ञापन मूल्य (रु.)	ब्याना राशि	ऑफर की वैधता	समापन की अवधि
		63181032.24	1263600.00	60 दिन	12 महीने
		सामान प्रकृति का कार्यः "ट्रैक के काम के अलावा कोई भी सिविल काम।"			
3	67-2026-27-ADEN-2-FZR	सहायक मंडल अभियंता- द्वितीय/फिरोजपुर के तहत 30 स्टेशनों और मंडल अभियंता-मुख्यालय/फिरोजपुर के तहत 55 स्टेशनों पर टैक्टाइल पाथ, पार्किंग एरिया, दिव्यांगजन टॉयलेट, COP आदि जैसी MEA और दिव्यांगजन सुविधाएं उपलब्ध कराना।			
		विज्ञापन मूल्य (रु.)	ब्याना राशि	ऑफर की वैधता	समापन की अवधि
		75789890.69	1515800.00	60 दिन	12 महीने
		सामान प्रकृति का कार्यः "ट्रैक के काम के अलावा कोई भी सिविल काम।"			

नोट : 1. निविदा डालने से पहले, निविदाकर्ता निविदा के संबंध में जारी किए गए किसी भी शुद्धिपत्र की जॉच करेंगे।
2. हिन्दी में किसी भी त्रुटि हेतु अंग्रेजी वर्जन का अवलोकन करे, तथा अंग्रेजी वर्जन ही मान्य होंगे।

2534/26

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

डीसी ने बाढ़ प्रभावित बेला कॉलोनी में आवाजाही और निर्माण कार्यों पर लगाई रोक

राजौरी, 23 जुलाई। जिला मजिस्ट्रेट राजौरी अभिषेक शर्मा ने 18-19 जुलाई 2026 की रात राजौरी तवी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद प्रभावित बेला मार्केट और बेला कॉलोनी क्षेत्र में आम लोगों और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने तथा सभी प्रकार के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संबंधित प्रावधानों के तहत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। जीपीएस आधारित मैपिंग और भू-संदर्भित

बाढ़ आंकड़ों से पुष्टि हुई है कि बाढ़ का पानी नदी के सामान्य किनारों से आगे तक फैल गया, जिससे भूमि कटाव, जमीन की अस्थिरता और जन-धन के लिए लगातार खतरा बना हुआ है।

आदेश के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों में बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति या नागरिक वाहन के प्रवेश, आवागमन और एकत्र होने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध रहेगा।

सभी प्रकार के निर्माण कार्य, जिनमें खुदाई, मिट्टी भराई, नींव निर्माण, भवन निर्माण या मरम्मत, निर्माण सामग्री डालना, मशीनरी की तैनाती तथा भूमि उपयोग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन शामिल है, पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति तथा सक्षम तकनीकी अधिकारियों की मंजूरी के बिना कोई भी निर्माण गतिविधि नहीं की जा सकेगी।

ये प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक जल विज्ञान, नदी प्रवाह और भूमि उपयोग से संबंधित विस्तृत अध्ययन पूरा नहीं हो जाता तथा संवेदनशील क्षेत्रों का वैज्ञानिक आधार पर सीमांकन नहीं कर लिया जाता।

जिला प्रशासन ने राजौरी तवी नदी के खतरनाक हिस्सों की ओर जाने वाले सभी मुख्य मार्गों, संपर्क मार्गों और पैदल रास्तों पर बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजौरी, तहसीलदार राजौरी और संबंधित अभियंत्रण विभागों को संयुक्त रूप से जलमग्न क्षेत्रों का सीमांकन करने, जारी निर्माण कार्यों की पहचान करने, आवश्यकतानुसार उन्हें तत्काल बंद कराने तथा 24 घंटे के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, चिकित्सा दल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत एजेंसियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजौरी को पुलिस बल की तैनाती, जांच चौकियों तथा राजस्व-पुलिस की संयुक्त गश्त के माध्यम से आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता।

जिला प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा के हित में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

डीसी कुलगाम ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यों की समीक्षा की

कुलगाम, 23 जुलाई। उपायुक्त डीसी कुलगाम शहजाद आलम ने आज जिले में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले एफसीएस एंड सीए विभाग के कार्यों और प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, राशन वितरण आधार सीडिंग ई-केवाईसी की प्रगति, शिकायत निवारण तथा समग्र सेवा वितरण की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने राशन कार्ड प्रबंधन, खाद्यान्न वितरण तथा पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की स्थिति का जायजा लिया। डीसी ने जिले के

सभी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार बनाए रखने और उनकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं के समय पर वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। जवाबदेही और कार्यकुशलता पर बल देते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करें निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र लाभार्थी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त कुलगाम अल्ताफ अहमद खान, अतिरिक्त उपायुक्त कुलगाम विकार अहमद गिरी सहायक निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कुलगाम इफ्तिखार अहमद खान, तहसील आपूर्ति अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

संपादकीय

पॉलीथिन के खिलाफ विफल जंग

जम्मू-कश्मीर में पॉलीथिन थैलों पर प्रतिबंध कागजों में तो मौजूद है, लेकिन जमीन पर उसका असर बेहद सीमित दिखाई देता है। किसी भी बाजार से होकर गुजरिए, आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित पतले प्लास्टिक बैग हर जगह नजर आते हैं—सब्जियों में लिपटे हुए, रेहड़ियों से लटकते हुए और दुकानदारों द्वारा बिना किसी हिचकिचाहट के ग्राहकों को थमाए जाते हुए। प्रतिबंध वास्तविक है, लेकिन उसका पालन नहीं।

इस स्थिति का कारण समझना कठिन नहीं है। प्रतिबंधित पॉलीथिन सस्ती है, और महंगाई के दौर में सस्ती चीज का महत्व बहुत अधिक है। अधिकृत विकल्प महंगे पड़ते हैं, और एक रेहड़ीवाले या छोटे दुकानदार के लिए गणित सीधा है—पर्यावरण जैसी अमूर्त अवधारणा की रक्षा करने की बजाय कभी-कभार लगने वाले जुर्माने का जोखिम उठा लेना ज्यादा आसान है। जब नीति इस मूल आर्थिक असंतुलन को दूर नहीं करती, तब रोजी-रोटी हमेशा पर्यावरण पर भारी पड़ती है।

जम्मू नगर निगम पूरी तरह निष्क्रिय नहीं है। छापे पड़ते हैं, जब्ती होती है और हजारों किलोग्राम अवैध पॉलीथिन बरामद की जाती है। लेकिन ये केवल सतही कार्रवाई है। असली आपूर्ति श्रृंखला लखनपुर सीमा से होकर चलती है, जहां बाहरी राज्यों से पॉलीथिन तस्करी के जरिए जम्मू-कश्मीर में लाई जाती है और फिर दुकानदारों तथा रेहड़ीवालों तक पहुंचाई जाती है। यह एक संगठित, कर-मुक्त और लगभग अनियंत्रित कारोबार है, जिस पर समय-समय पर होने वाले छापों का असर बहुत कम पड़ता है। इस श्रृंखला में शामिल हर व्यक्ति—तस्कर से लेकर छोटे विक्रेता तक—जानता है कि पकड़े जाने की संभावना कम है और पकड़े जाने की कीमत उससे भी कम।

मांग पक्ष पर भी नियंत्रण नहीं है। उपभोक्ताओं पर जुर्माने की चेतावनी देने वाले नगर निगम के आदेश भी प्रभावी साबित नहीं हुए। लोग आज भी प्रतिबंधित थैलों में सामान घर ले जाते हैं, क्योंकि न तो कोई वास्तविक डर है और न ही ऐसा वैकल्पिक विकल्प, जिसे पर्याप्त मजबूती से आगे बढ़ाया गया हो। इस बीच जम्मू नगर निगम एक प्रभावी प्रवर्तन एजेंसी से अधिक दर्शक की भूमिका में दिखाई देता है—ऐसे अभियान चलाते हुए जो सुर्खियां तो बनाते हैं, लेकिन व्यवहार में बहुत कम बदलाव लाते हैं।

कमी प्रयासों की नहीं, रणनीति की है। जब्ती और जुर्माने केवल लक्षणों का उपचार करते हैं; वे उस आपूर्ति तंत्र को नहीं छूते जो इस समस्या को लगातार पोषण दे रहा है। यदि पॉलीथिन एक ज्ञात सीमा बिंदु से जम्मू-कश्मीर में प्रवेश कर रही है, तो यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान संभव है—कड़ी जांच चौकियां, माल की निगरानी और सीमा पार होने वाली सामग्री के लिए जवाबदेही तय करके। यदि अवैध पॉलीथिन कानूनी विकल्पों की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी है, तो उसका भी समाधान है—अनुपालन करने वाले विकल्पों पर सब्सिडी दी जाए और छोटे विक्रेताओं के लिए वैध विकल्प वास्तव में प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, न कि उनसे ऐसी व्यवस्था में अनुपालन की उम्मीद की जाए जहां अनुपालन स्वयं घाटे का सौदा हो।

जन-जागरूकता महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल तब जब उसके साथ दांतों वाला प्रवर्तन भी हो। कोई दुकानदार जिसने वर्षों तक प्रतिबंधित थैले बिना किसी परिणाम के इस्तेमाल किए हों, वह केवल पर्चे बांटने से नहीं रुकेगा।

उसका व्यवहार तब बदलेगा जब उसे यह निश्चित लगे कि आपूर्ति रास्ते में रोकी जाएगी, जुर्माना वास्तव में लगेगा और यह कोई मौसमी अभियान नहीं बल्कि लगातार चलने वाली मुहिम है।

समस्या का पैमाना उसी स्तर की गंभीर प्रतिक्रिया की मांग करता है। एक संगठित तस्करी नेटवर्क और गहराई से जमी बाजार की आदत के खिलाफ आधे-अधूरे उपाय हमेशा वही परिणाम देंगे—एक और छापा, एक और जब्ती, कुछ और सुर्खियां, और अगली सुबह हर रेहड़ी पर फिर वही पॉलीथिन बैग। जम्मू-कश्मीर को ऐसी रणनीति की जरूरत है जो समस्या के आकार के अनुरूप हो, न कि ऐसी जो केवल सक्रिय दिखाई दे लेकिन वास्तविकता में कुछ भी न बदले।

एक लाख से दो लाख- उद्यमी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं

श्री चिराग पासवान

जब 2020 में कोविड-19 महामारी ने लोगों के जीवन और आजीविका पर बुरा असर डाला, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महसूस किया कि फिर से पूर्वस्थिति बहाल करने की प्रक्रिया केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे सबसे छोटे उत्पादकों और उद्यमों तक भी पहुँचना चाहिए, खासकर उन उद्यमों तक, जो भारत के गांवों और छोटे शहरों में कार्यरत हैं।

इस उद्देश्य के साथ, उस साल, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत

पीएमएफएमई के ऋण से जुड़े घटक के तहत अब तक दो लाख से अधिक मंजूरियां दी जा चुकी हैं। यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पीछे वे उद्यमी हैं, जो औपचारिक ऋण-प्रणाली से जुड़े हैं और जिन्हें अपने उद्यम-निर्माण का असली मौका मिला है। यह जश्न मनाने लायक उपलब्धि है और उन लोगों का सम्मान करने का अवसर है, जिन्होंने इसे संभव बनाया है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना शुरु की गई थी। इसकी शुरुआत खाद्य अर्थव्यवस्था के उस हिस्से के साथ हुई, जो लंबे समय तक औपचारिक वित्त और संस्थागत समर्थन से बाहर रहा था- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, जो पहले ही उत्पादन व बिक्री कर रहे थे और कुछ लोगों को रोजगार दे रहे थे, लेकिन जिनके पास आगे बढ़ने के लिए आवश्यक पूंजी या मार्गदर्शन नहीं था। यह योजना उस विश्वास को प्रतिबिंबित करती है, जिसे प्रधानमंत्री लगातार मानते रहे हैं, कि भारत की वृद्धि इसके आधार से शुरू होनी चाहिए, यानि उन लोगों के बीच, जो अपने खुद के उद्यम शुरू करना चाहते हैं।

पीएमएफएमई के ऋण से जुड़े घटक के तहत अब तक दो लाख से अधिक मंजूरियां दी जा चुकी हैं। यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पीछे वे उद्यमी हैं, जो औपचारिक ऋण-प्रणाली से जुड़े हैं और जिन्हें अपने उद्यम-निर्माण का असली मौका मिला है। यह जश्न मनाने लायक उपलब्धि है और उन लोगों का सम्मान करने का अवसर है, जिन्होंने इसे संभव बनाया है।

इनमें सबसे पहले व्यक्ति श्री जमनालाल पाटीदार थे, जिनका आवेदन पीएमएफएमई के तहत सबसे पहले मंजूर किया गया था। 10वीं पास इस उद्यमी के पास खाद्य प्रसंस्करण का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन इन्होंने ?10 लाख के निवेश के साथ धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू की। इस योजना की मदद से उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन की सुविधा मिली और उनका विचार एक कामयाब व्यवसाय में बदल गया, जो आज पाँच से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है।

उसकी कहानी एक सरल बात बताती है। उद्यमिता केवल अच्छे परिवार या अच्छे शिक्षा प्राप्त लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने विचार को क्रियान्वित करने के लिए वित्त, तकनीक और सहायता प्राप्त कर सकता है। आम भारतीयों को उद्यम बनाने और दूसरों को रोजगार देने में सक्षम बनाकर, पीएमएफएमई योजना प्रधानमंत्री के उस विज़न को आगे बढ़ा रही है, जिसमें नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वाले में बदलने की बात कही गयी है।

भारत में लंबे समय से छोटे स्तर पर काम करने वाले लाखों कुशल उद्यमी मौजूद रहे हैं, जो विशिष्ट स्थानीय उत्पाद बनाते हैं। इनमें से कई लोगों के पास किफायती वित्त, आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता प्रमाणन और संगठित बाजार तक पहुँच की कमी थी। यह योजना ऋण से जुड़ी सहायता, क्षमता निर्माण, साझा अवसंरचना, ब्रांडिंग और बाजार पहुँच के जरिये इन कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना था, ताकि उनके पास आगे बढ़ने का वास्तविक अवसर हो।

इस बदलाव में महिलाओं की प्रमुख भूमिका रही है। ऋण से जुड़ी दो लाख मंजूरियों में से लगभग 44 प्रतिशत का लाभ महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को मिला है, जबकि चार लाख से अधिक स्व-सहायता समूह के सदस्यों ने अपने व्यवसाय को मजबूत और उन्नत करने के लिए शुरुआती पूंजी प्राप्त की है। पूरी योजना से 20,300 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है और लगभग छह लाख लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। 75,000 से अधिक इकाइयाँ उद्यम पंजीकरण और एफएसएसएआई व जीएसटी के तहत अनुपालन के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुकी हैं। कई महिलाओं के लिए इसका मतलब है, घर या समुदाय में अभ्यास किये जाने वाले हुनर को ऐसे मान्यता प्राप्त उद्यमों में बदलना, जहाँ उन्हें वित्त, तकनीक और बड़े बाज़ारों तक पहुँच मिल सके। इस बदलाव में अन्य महिलाओं को मदद करना अगले चरण की प्राथमिकता होनी चाहिए।

इनमें से प्रत्येक संख्या के पीछे एक बड़ा लाभ छिपा है। एक कामकाजी उद्यमी किसान की उपज खरीदता है, हर फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है और अधिक मूल्य वहीं रखता है जहां इसे बनाया गया है। एक स्थानीय फ़सल ब्रांडेड उत्पाद बन जाती है। एक घरेलू कौशल स्थायी रोजगार बन जाता है। समय के साथ, एक जिले की पहचान उसके द्वारा बनाई गयी चीज़ों से होने लगती है। व्यावहारिक तौर पर यही वोकल फॉर लोकल है, एक समय में एक उद्यम।

पीएमएफएमई के तहत दो लाखवीं मंजूरी रांची के श्री इंदरजीत सिंह को मिली, जो एक बेकरी बना रहे हैं और सपना देखते हैं कि उनके केक और पेस्ट्री एक दिन पूरे झारखंड में मशहूर होंगे। पूर्व के पाटीदार की तरह, वे छोटे उद्यम और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ शुरुआत कर रहे हैं और उन्हें योजना का सहारा भी मिल रहा है। वे पहली पीढ़ी के हजारों उद्यमियों में से एक हैं, जिन्हें पीएमएफएमई योजना पहली मंजूरी से एक सफल उद्यम तक पहुंचा रही है। अगर पाटीदार दिखाते हैं कि यह यात्रा कितनी दूर तक जा सकती है, तो सिंह दिखाते हैं कि यह अभी और गति पकड़ रही है।

आगे के रास्ते का यही रूप है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण के लिए औपचारिक ऋण को सुविधाजनक बनाना पहला काम था, और मुश्किल लेकिन ज्यादा संतोषजनक काम यह है कि हर मंजूरी को वास्तव में दिए गए ऋण में बदलना, और हर ऋण से एक ऐसा व्यवसाय बनाना, जो कारोबार करे और लंबे समय तक चलता रहे। मंजूरी से दरवाजा खुलता है; हमारा काम हर उद्यमी को उस दरवाजे से गुजरने में मदद करना है, ताकि वे कुछ ऐसा बनाएं, जो लंबे समय तक चले।

पीएमएफएमई के अगले चरण की दिशा यही होनी चाहिए। हम होनहार उद्यमों तक तेज़ी से ऋण पहुँचाएँगे, बेहतर तकनीक और पैकेजिंग अपनाने में उनकी मदद करेंगे, बाज़ार तक उनकी पहुँच का विस्तार करेंगे और इनमें से बहुत से उद्यमियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचने के लिए तैयार करेंगे। हम उद्यमियों के साथ मंजूरी के केवल पहले ही नहीं, बल्कि मंजूरी के बाद भी खड़े रहेंगे, उन्हें लगातार ऐसा सहयोग देंगे, जिससे उनका पहला ऋण स्थायी आजीविका का एक ज़रिया बन जाए।

कुल मिलाकर, ये दो लाख मंजूरियां प्रशासनिक उपलब्धि से कहीं ज्यादा हैं। हर ऐसा उद्यम, जो जड़ें जमा लेता है, अपने आस-पास की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। यह पास के खेतों से खरीदारी करता है, घर के पास आय सृजित करता है और महिलाओं और युवा भारतीयों को खुद का व्यवसाय शुरू करने का आत्मविश्वास देता है।

जब हम पाटीदार की धनिया इकाई को देखते हैं, तो सबक सरल है। पीएमएफएमई के तहत पहली मंजूरी एक ऐसे व्यक्ति को मिली, जिसके पास न तो स्थापित फैक्टरी थी और न ही कोई विशेष डिग्री। उनके पास केवल एक विचार था और काम करने की इच्छा थी और योजना ने उन्हें पहुँच की सुविधा दी। दो लाख मंजूरियों के बाद, ये अवसर अब पूरे देश के उद्यमियों तक पहुँच चुके हैं। अब हमारा काम है कि हम और अधिक लोगों को ऐसे व्यवसाय बनाने में मदद करें, जो चलते रहें, दूसरों को रोजगार दें और वहीं मूल्य बनाएं, जहां से उन्होंने शुरू किया है।

(लेखक केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं)

बिहार में यूरिया एवं डीएपी की स्थिति- चुनौती, कारण और समाधान

डॉ. अरविंद नाथ तिवारी

बिहार देश के प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों में से एक है, जहां राज्य की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। धान, मक्का, गन्ना, गेहूं, दलहन, तिलहन तथा सब्जियों की खेती यहां की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है।

इन फसलों की अच्छी पैदावार के लिए समय पर और संतुलित मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है। विशेष रूप से यूरिया और डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) किसानों की सबसे अधिक उपयोग में आने वाली खाद हैं। हर वर्ष खरीफ और रबी सीजन के दौरान इनकी मांग कई गुना बढ़ जाती है। यदि समय पर उर्वरक उपलब्ध नहीं होते तो बुवाई, पौधों की वृद्धि और अंततः उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वर्तमान खरीफ मौसम में बिहार के कई जिलों से यूरिया और डीएपी की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। अनेक स्थानों पर किसानों को उर्वरक प्राप्त करने के लिए घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने, कृत्रिम कमी पैदा करने और कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आई हैं। इससे किसानों की आर्थिक परेशानी बढ़ी है और खेती की लागत में भी वृद्धि हुई है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह स्थिति और अधिक कठिन हो जाती है क्योंकि उनके पास अतिरिक्त संसाधन नहीं होते।

विशेषज्ञों के अनुसार बिहार में उर्वरकों की कमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि राज्य में यूरिया और डीएपी का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता। बिहार अपनी अधिकांश आवश्यकता अन्य राज्यों के उर्वरक संयंत्रों से प्राप्त करता है। इन उर्वरकों की आपूर्ति रेलवे रैक, सड़क परिवहन और गोदामों के माध्यम से होती है। यदि रेलवे रैक समय पर उपलब्ध नहीं होते या परिवहन व्यवस्था बाधित होती है तो जिलों तक उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। कई बार गोदामों से खुदरा विक्रेताओं तक वितरण में भी विलंब होता है, जिससे कृत्रिम संकट की स्थिति बन जाती है।

उर्वरक संकट का एक अन्य कारण असंतुलित उपयोग भी है। अनेक किसान वैज्ञानिक सलाह के बजाय केवल यूरिया पर अधिक निर्भर रहते हैं। इससे यूरिया की मांग अचानक बढ़ जाती है, जबकि फसल को संतुलित पोषण नहीं मिल पाता। कृषि वैज्ञानिक लगातार सलाह देते रहे हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग ही अधिक उत्पादन और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय है। केवल यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है और दीर्घकाल में उत्पादन क्षमता भी घट सकती है।

केंद्र और राज्य सरकार समय-समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाती रही हैं। उर्वरक की आपूर्ति की नियमित निगरानी, जिला स्तर पर भंडारण की समीक्षा, कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी तथा लाइसेंसधारी विक्रेताओं का निरीक्षण जैसे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कई जिलों में कृषि एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खाद-बीज दुकानों की जांच भी की जा रही है, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

इसी क्रम में हाल ही में वाल्मीकिनगर के सांसद सुनील कुमार ने नई दिल्ली में उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय की संयुक्त सचिव वंदना प्रेयसी तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निदेशक (मूवमेंट) अभय कुमार से मुलाकात कर बिहार, विशेष रूप से वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि खरीफ सीजन में उर्वरकों की कमी के कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से खेती का पूरा चक्र प्रभावित हो सकता है इसलिए आवश्यक है कि बिहार को उसकी मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। बैठक के दौरान केंद्रीय अधिकारियों ने सांसद को आश्वस्त किया कि बिहार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यूरिया एवं डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि रेलवे रैक की उपलब्धता बढ़ाने, वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाने तथा समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है।

दीर्घकालिक समाधान के लिए केवल आपूर्ति बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा। बिहार में उर्वरक वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा तकनीक आधारित बनाना होगा। प्रत्येक जिला में मांग के अनुरूप अग्रिम भंडारण, ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, नियमित निरीक्षण तथा दोषी विक्रेताओं पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है। साथ ही किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैविक खाद, हरी खाद और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग को भी बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता कम हो सके।

बिहार की कृषि व्यवस्था की मजबूती के लिए यूरिया और डीएपी की नियमित, पर्याप्त और समय पर उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। यदि केंद्र और राज्य सरकार बेहतर समन्वय के साथ आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करें, परिवहन और वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाएं, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करें तथा किसानों को वैज्ञानिक एवं संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूक करें, तो उर्वरक संकट पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ेगी, मिट्टी की उर्वरता सुरक्षित रहेगी और बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था भी अधिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेगी।

किराए की कोख की दुकानों पर अंकुश

-प्रमोद भार्गव

केंद्र सरकार 'किराए की कोख' यानी सरोगेसी मदर की क्लीनिक के नाम पर खुली मनमानी दुकानों पर अंकुश लगने जा रही है। अब कुकुरमुत्तों की तरह देशभर में खुल रही नई दुकानें खोलने पर सख्ती बरती जाएगी। सरोगेसी केंद्रों और इनमें होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने इसमें पंजीयन और संचालन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत इन केंद्रों को अब उपग्रहों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

अब केवल राष्ट्रीय पोर्टल और ऑनलाइन आवेदन ही होंगे। इस पर निगरानी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से होगी। कागजी आवेदन व दस्तावेजीकरण की सुविधा पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। ये क्लीनिक अन्य दूसरे क्लीनिक को चिकित्सा सुविधा नहीं दे सकेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि नए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।

दरअसल, किराए की कोख का व्यवसायीकरण हो रहा है। यह इस तथ्य से पता चला कि कुछ ही सालों के भीतर देश में 35 से 50 प्रतिशत केंद्रों की संख्या बढ़ गई। इसी अनुपात में देश-विदेश में ठगी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। हैदराबाद में ऐसा गिरोह पकड़ा गया, जो 2 से 4 लाख में कोख किराए पर लेकर 30 लाख रुपए तक में बेच देते थे। यहां तक कि विदेशों से भी शुक्राणु दानदाता लाए गए। यानी देश के बाहर भी बच्चे बेचे गए। हालांकि 2025 में सरकार ने शुक्राणु दाता नियमों में बदलाव किया था लेकिन कारोबारियों ने इन नियमों की अनदेखी की। नाबालिग और अविवाहित लड़कियों की कोख का भी अवैध इस्तेमाल किया गया। भारत में कोख किराए से लेने का खर्च 10 से 25 लाख है, जबकि विदेशों में 80 लाख से डेढ़ करोड़ रुपए तक ह

। इसलिए सरोगेसी क्लीनिकों में किराए की कोख अवैध कारोबार का बड़ा धंधा बनती जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु में सरोगेसी के अनेक ठगी के मामले सामने आए हैं। इसलिए सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ा। इसके पहले 2025 में लिव इन और समलैंगिक युगलों को किराए की कोख के जरिए माता-पिता बनने का अधिकार देने से साफ मना कर दिया था।

अब ऑनलाइन जानकारी होने से निगरानी तंत्र के पास सरोगेसी क्लीनिक संचालन व नवीनीकरण संबंधी जानकारी हर वक्त सामने होगी। इससे अनियमितता को आसानी से चिन्हित कर लिया जाएगा। क्लीनिक के पास क्या वैध दस्तावेज हैं, इसकी भी पुख्ता जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी कमी पाए जाने पर संस्था को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। इन केंद्रों के कर्मचारियों और बच्चों के जन्म की जानकारी भी मिलती रहेगी। सरकार इन नियमों को एक साथ लागू करने की बजाय चरणबद्ध अमल में लाएगी। वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के प्रयोग की अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो

। अर्थात इस हालात में वैवाहिक जोड़ा सरोगेसी मदर का साहरा ले सकता है। कानून के अनुसार यह भी बाध्यकारी शर्त है कि किराए की कोख देने वाली महिला विवाहित होनी चाहिए और कम-से-कम उसका एक बच्चा भी हो। साथ ही पति की आयु 26 से 55 वर्ष और पत्नी की आयु 23 से पचास वर्ष के बीच होना आवश्यक है।

किराए की कोख के कानून में परिवर्तन इसके बढ़ते अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने की दृष्टि से किया गया है। अब केवल निःसंतान दंपति जो बच्चे पैदा करने में शारीरिक रूप से अक्षम हैं, वे अपने किसी करीबी रिश्तेदार की मदद ले सकते हैं। इस सुविधा को कानूनी भाषा में 'अल्ट्रस्टिक सर्जरी सरोगेसी' कहा जाता है। भारत दुनिया के दंपतियों के लिए किराए की कोख का बड़ा व्यावसायिक नाभिकेंद्र बनता जा रहा है, जो सुविधा वास्तविक जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई थी, वह अमीर दंपतियों के लिए शौक में तब्दील होती जा रही है। सूचना तकनीक के बाद भारत में प्रजनन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसमें किराए पर कोख दिए जाने का धंधा भी शामिल है। चिकित्सा पर्यटन के बहाने विदेशी पर्यटक भारत प्रसूति पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं।

भारत में किराए की कोख का कारोबार अरबों डॉलर का हो गया है लेकिन यह धंधा अंततः प्रकृति की प्रतिरूप महिला की कोख पर टिका है, ठीक उसी तरह जिस तरह, उदारवादी अर्थव्यवस्था प्रकृति के गर्भ में समाई खनिज संपदाओं के दोहन पर टिकी है। इस धंधे की भारी कीमत उन महिलाओं को चुकानी पड़ी है, जिन्हें अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए हर हाल में धन की जरूरत रहती है। अतएव 2016 में प्रजनन सहायक तकनीक विधेयक लाकर केंद्र सरकार ने इस गोरखधंधे पर अकुंश लगाने की पहल कर दी थी। जो एक सही कदम रहा है। लेकिन इस कानून से उन्हें परेशानी है, जिन्होंने स्त्री की आर्थिक कमजोरी को वस्तु में डालकर उसकी कोख को बाजार के हवाले कर दिया है। वे यह भी दलील दे रहे हैं कि कठोर कानून से विदेशी मुद्रा का आगमन रुक जाएगा।

सरोगेसी मां बनने के लिए महिला को इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसके लिय जैविक माता-पिता के शुक्राणु और अण्डाणु को परखनली में निषेचित करने के बाद जब भ्रूण पनप जाता है, तब उसे अन्य स्त्री की कोख में प्रत्यारोपित किया जाता है। गर्भाधान का यही एकमात्र उपाय है। इसका शरीर पर विपरीत असर पड़ता है, इसके गर्भपात होने की 80 फीसदी आशंका रहती है। ऐसी 90 प्रतिशत प्रसूति शल्यक्रिया के जरिए होती हैं। ऐसे में महिला की जान का संकट भी बना रहता है। इस स्थिति में कोख किराए से देने वाली महिला का न तो कोई बीमा होता था, न ही उसके पति और बच्चों की कोई गारंटी लेता था। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी बड़ा सवाल था कि जैविक अविभावक यदि जन्म के बाद बच्चे को छोड़कर नौ-दो-ग्यारह हो जाते हैं तो उसके पालन-पोषण की जबावदेही किसकी थी? यदि नवजात शिशु विकलांग या ऐसी लाइलाज बीमारी के साथ पैदा होता है और जैविक माता-पिता उसे लेने से इनकार कर देते हैं तो उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेता? ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, जो किश्तों पर कोख किराए पर देती थीं। ऐसी ही सुविधाओं के चलते भारत में किराए की कोख वैश्विक राजधानी बन गया था।

इस बाबत एक स्वयंसेवी संगठन के अध्ययन ने चौंकाने वाले सवाल भी उठाए थे। खासतौर से विदेशी धनवान जब किराए की कोख से संतान पाने के इच्छुक होते हैं तो वे भारत आकर एक साथ कई महिलाओं को गर्भधारण करा देते हैं। इनमें से कुछ महिलाओं में यह प्रयोग सफल हो जाता है तो वह किसी एक महिला को छोड़ बाकी का गर्भपात करा देते हैं। गर्भपात कराई गई महिलाओं को कोई धन भी नहीं दिया जाता था। यह सरासर अन्याय व अनैतिकता थी। इसी अध्ययन से खुलासा हुआ था कि कोख की कीमत कई हजार डॉलर है लेकिन इस राशि में से सरोगेसी मां को महज 1 या 2 प्रतिशत धनराशि ही बामुश्किल मिल पाती है। बाकी अस्पताल के चिकित्सक और बिचौलिये हजम कर जाते थे।

अप्रवासी भारतीयों में सरोगेसी की मांग बहुत ज्यादा थी। यदि स्त्री स्वस्थ व सुंदर होने के साथ उच्च जाति और उत्तम पारिवारिक पृष्ठभूमि से होती थी तो उसे ज्यादा पैसा दिया जाता था। अप्रवासी दंपति भारत आकर किराए की कोख द्वारा बच्चा पैदा करना इसलिए भी अच्छा मानते थे क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक स्तर पर अपने को भारत से जुड़ा पाते थे, नतीजतन भारत में सरोगेसी की मांग तेजी से बढ़ रही रही थी। वर्तमान में अमीर घरों की स्त्रियां शौक के लिए या बच्चा पैदा करने के कठिन दायित्व से बचने के लिए किराए की कोख से संतान पैदा कर रही हैं। अतएव यह कारोबार निरंतर बढ़ रहा था। यहां तक कि नाबालिग और अविवाहित लड़कियां भी इस धंधे में धन कमाने के लिए उतरती चली आ रही थीं। इसलिए इस कानून में नए बदलाव जरूरी थे।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

पुरुष एकल वर्ग में डॉ. विशाल रस्तोगी, युगल वर्ग में आयुष और गौरव की जोड़ी ने जीता खिताब

एजेंसी

मुरादाबाद। भारत विकास परिषद शिवाजी शाखा द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोनकपुर स्पोर्टस स्टेडियम में बैडमिंटन प्रीमियर लीग-2026 संपन्न हुई। जिसमें पुरुष एकल वर्ग में डॉ. विशाल रस्तोगी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए खिताब जीता, जबकि अनुपेंद्र सिंह उपविजेता रहे। पुरुष युगल वर्ग में आयुष और गौरव की जोड़ी ने शानदार तालमेल के दम पर विजेता ट्रॉफी हासिल की। साकेत और डॉ. रोमिल सिंघल की जोड़ी को उपविजेता से संतोष करना पड़ा। महिला एकल में याशिका ने विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया, जबकि ज्योति उपविजेता रहीं। महिला युगल में स्वाति और याशिका की जोड़ी ने बाजी मारी, वहीं ज्योति और प्राची की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही। समापन समारोह में शाखा अध्यक्ष अनुष कुमार बंसल ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन खेल भावना, स्वास्थ्य और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देते हैं। इस दौरान रूपांशु सिंघल, नितिन, दीपांशु, आशु, रक्षित, हेमंत, विवेक सहित शाखा के कई सदस्य मौजूद रहे।

डूरंड कप का आगाज 25 जुलाई से, उद्घाटन मैच में मोहन बागान-ईस्ट बंगाल की टक्कर

कोलकाता। भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें इंडियन ऑयल डूरंड कप का आगाज 25 जुलाई से होगा। प्रतियोगिता का फाइनल 23 अगस्त को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। कोलकाता में आयोजित कर्टेन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में टूर्नामेंट की तैयारियों और आयोजन की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रेसवार्ता में डूरंड कप आयोजन समिति के अध्यक्ष तथा पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, आयोजन समिति के उपाध्यक्ष मेजर जनरल दिनेश कुमार सिंह, पश्चिम बंगाल सरकार में खेल मंत्री इंद्रनील खां, राज्य सरकार में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश पांडेय, खेल सचिव अभिनेंद्र सिंह सहित सेना और आयोजन समिति के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस बार डूरंड कप में 24 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें छह समूहों में विभाजित किया गया है। ग्रुप चरण के बाद सभी छह समूहों की विजेता टीमों के साथ सर्वश्रेष्ठ दो उपविजेता क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। क्वार्टर फाइनल 17 और 18 अगस्त को खेले जाएंगे। इसके बाद सेमीफाइनल और 23 अगस्त को फाइनल मुकाबला होगा।

राष्ट्रमंडल खेल : पहले दिन लॉन बॉल्स में भारत के दो मुकाबले, पुतुल सोनोवाल की टक्कर विश्व चैंपियन से

ग्लासगो। राष्ट्रमंडल खेल-2026 के पहले दिन 23 जुलाई को भारतीय लॉन बॉल्स टीम के दो मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष एकल वर्ग में भारत के पुतुल सोनोवाल का सामना कनाडा के दिग्गज विश्व चैंपियन खिलाड़ी ryan बेस्टर से होगा, जबकि महिला युगल वर्ग में पिंकी और रूपा रानी तिर्की की जोड़ी माल्टा के खिलाफ चुनौती पेश करेगी। पुरुष एकल स्पर्धा के सेक्शनल प्ले मुकाबले में विश्व रैंकिंग 21 के पुतुल सोनोवाल का मुकाबला विश्व बॉल्स हॉल ऑफ फेम में शामिल और मौजूदा विश्व चैंपियन ryan बेस्टर से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:15 बजे स्कॉटिश इवेंट कैंपस (एसईसी) में खेला जाएगा। महिला युगल स्पर्धा में विश्व रैंकिंग 57 की पिंकी और विश्व रैंकिंग 47 की रूपा रानी तिर्की की भारतीय जोड़ी सेक्शनल प्ले में माल्टा की कोनी रिक्सन और रेबेका रिक्सन के खिलाफ उतरेगी। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 4:50 बजे खेला जाएगा।

टी-20 में जीत की राह पर लौटने उतरेगा भारत, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में अय्यर की अग्निपरीक्षा

हरारे। लगातार टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम शुरू हो रही तीन मैचों की टी-20 सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत की पटरी पर लौटने के इरादे से मैदान में उतरेगी। कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में पहली सीरीज जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगे, जबकि युवा भारतीय टीम के सामने हालिया असफलताओं को पीछे छोड़ने की चुनौती होगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने शुरुआती सात टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में छह मैच गंवाए हैं। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद जिम्बाब्वे दौरा टीम के लिए आत्मविश्वास हासिल करने का सुनहरा मौका है। हालांकि भारत इस सीरीज में प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन हार टीम के ड्रेसिंग रूम पर बड़ा असर डाल सकती है। इस दौरे पर मुख्य कोच गौतम गंभीर की जगह वीवीएस लक्ष्मण टीम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में टीम संयोजन और रणनीति पर भी सभी की नजरें रहेंगी।

फीफा विश्व कप-2026 की ड्रीम इलेवन घोषित, मेसी, एम्बाप्पे और हालैंड को मिली जगह

एजेंसी

ज्यूरिख। फीफा विश्व कप 2026 की प्रशंसकों द्वारा चुनी गई ड्रीम इलेवन की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे, नॉर्वे के एरलिंग हालैंड और इंग्लैंड के जूद बेलिंघम जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को जगह मिली है। विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित करने वाले केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा को भी ड्रीम इलेवन में शामिल किया गया है। 40 वर्षीय वोजिन्हा को गोलकीपर के लिए हुए प्रशंसकों के मतदान में 39.6 प्रतिशत वोट मिले। उन्होंने विश्व कप में पदार्पण करने वाले केप वर्डे के लिए शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि, टूर्नामेंट का गोल्डन ग्लव पुरस्कार स्पेन के उनाई सिमोन को मिला था, जिसका चयन फीफा के तकनीकी समूह ने किया था।विश्व कप

से पहले पुर्तगाल के दूसरे डिवीजन क्लब चावेस छोड़ने के बाद वोजिन्हा किसी क्लब से नहीं जुड़े थे। इसके बावजूद उन्होंने विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्पेन के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ में सात शानदार बचाव किए। इसके अलावा उन्होंने अंतिम-32 मुकाबले में अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय तक खेलने के लिए मजबूर करने में भी अहम भूमिका निभाई। नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एरलिंग हालैंड को फॉरवर्ड खिलाड़ियों के मतदान में 27.5 प्रतिशत वोट मिले। हालैंड ने पांच मैचों में सात गोल दागे और अपनी टीम को पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल में पांच बार की चैंपियन ब्राजील के खिलाफ 2-1 की जीत में दो गोल किए थे। नॉर्वे का सफर इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ समाप्त हुआ। ड्रीम इलेवन में हालैंड और वोजिन्हा के अलावा लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे, जूद बेलिंघम, रोद्री, माइकल ओलिसे, पेड्रो पोरो, लिसांड्रो मार्टिनेज, दायो उपामेकानो और मार्क कुकुरेला को भी स्थान मिला है।

फीफा विश्व कप 2026 ड्रीम इलेवन

गोलकीपर: वोजिन्हा (केप वर्डे)

डिफेंडर: पेड्रो पोरो (स्पेन), लिसांड्रो मार्टिनेज (अर्जेंटीना), दायो उपामेकानो (फ्रांस), मार्क कुकुरेला (स्पेन)

मिडफील्डर: रोद्री (स्पेन), माइकल ओलिसे (फ्रांस), जूद बेलिंघम (इंग्लैंड)

ताइक्वांडो कलर बेल्ट टेस्ट में 50 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग

एजेंसी

मुरादाबाद। शिशु वाटिका ताइक्वांडो एकेडमी में आयोजित कलर बेल्ट टेस्ट में करीब 50 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। बेल्ट प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अगस्त माह में होने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो टूर्नामेंट में प्रतिभाग करेंगे। जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव शावेज अली ने बताया कि येलो बेल्ट में दिव्यांशी अग्रवाल, पृष्ठ गुप्ता, सनमीत कौर, सिद्धांत प्रताप सिंह, आयुष, अदिति पुन, तबीनाह, अभिषेक, ओम शर्मा, आदित्य भटनागर, रानी, साक्ष, भूमि, सोहम, अमीर हुसैन, इरम फातिमा और ख्याति यादव सफल रहे। ग्रीन बेल्ट में हुसैन, रिदा, विनायक, लक्ष्मी, गर्वी, अक्षत और वंश ने सफलता पाई। जबकि ग्रीन वन बेल्ट में सेहल शर्मा, सर्जन, दक्ष, सुषमा और आदित्य दीप शामिल रहे। इसके

अलावा ब्लू बेल्ट में विकेश, रिया, सामर्थ, पंकज और अथर्व ने स्थान बनाया। ब्लू वन बेल्ट में प्रत्यक्ष वर्मा और युवराज सफल रहे। रेड बेल्ट में सुषमा और रेड वन बेल्ट में इलमा हसन व अदिति वर्मा ने सफलता हासिल की।

चाइना ओपन 2026: अंतिम-16 में हारकर बाहर हुईं पी.वी. सिंधु

एजेंसी

चांगझोउ। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु का चाइना ओपन 2026 में सफर अंतिम-16 दौर में ही समाप्त हो गया। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में मेजबान चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चेन यू फेई ने शानदार वापसी करते हुए सिंधु को 16-21, 22-20, 21-18 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

सिंधु ने मुकाबले की शानदार शुरुआत करते हुए पहला गेम अपने नाम किया। हालांकि दूसरे गेम में उनके पास मैच खत्म करने के चार मौके थे, लेकिन वह उनका फायदा नहीं उठा सकीं और चेन ने लगातार पांच अंक जीतकर मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया।

पहले गेम में चेन ने 12-6 की बढ़त बना ली थी, लेकिन सिंधु ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 16-16 से बराबर किया और इसके बाद लगातार अंक जुटाकर 21-16 से गेम जीत लिया। दूसरे गेम में सिंधु पूरी तरह नियंत्रण में नजर आईं और 20-17 की बढ़त के साथ उनके पास चार मैच प्वाइंट थे। लेकिन इसी

मोड़ पर चेन ने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार पांच अंक हासिल किए और 22-20 से गेम जीतकर मुकाबले को तीसरे गेम में पहुंचा दिया। निर्णायक गेम में भी सिंधु ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन अंतिम चरण में चेन यू फेई ने लगातार शानदार अंक जुटाए और 21-18 से गेम जीतते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 की स्वर्ण पदक विजेता चेन यू फेई अब क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन और वियतनाम की नगुएन थुई लिन्ह के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता से भिड़ेंगी। इस हार के साथ चाइना ओपन 2026 में भारत की अनुभवी शटलर पी.वी. सिंधु का अभियान समाप्त हो गया।

मप्र के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद का हॉकी इंडिया की विश्व कप टीम में चयन

एजेंसी

भोपाल। मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य हॉकी अकादमी के एसोसिएट खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद का चयन एफआईएच हॉकी विश्व कप बेल्जियम एवं नीदरलैंड-2026 के लिए घोषित भारतीय पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। यह विश्व कप 15 से 30 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा, जिसमें भारतीय टीम विश्व विजेता बनने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। जनसम्पर्क अधिकारी दुर्गेश रायकवार ने बताया कि विवेक सागर प्रसाद का भारतीय पुरुष हॉकी टीम में चयन उनकी निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके विवेक अब विश्व हॉकी के सबसे प्रतिष्ठित मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, भारतीय टीम की कप्तानी अनुभवी डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को सौंपी गई है, जबकि अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह उपस्थिति से टीम को मजबूती देंगे। मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने टीम को अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलित मिश्रण बताते हुए विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया है।

उन्होंने बताया कि भारत को विश्व कप के पूल-डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के विरुद्ध करेगी, इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड तथा 19 अगस्त को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से मुकाबला खेलेगी। मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी से जुड़े खिलाड़ी का विश्व कप टीम में चयन प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का विषय है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग

द्वारा संचालित खेल अकादमियां लगातार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार कर रही हैं, जिसका परिणाम देश की विभिन्न राष्ट्रीय टीमों में प्रदेश के खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी के रूप में सामने आ रहा है।

चौथी हॉकी इंडिया जूनियर महिला अकादमी चैंपियनशिप 24 जुलाई से, ग्वालियर करेगा मेजबानी

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी की उभरती प्रतिभाओं को मंच देने वाला चौथा हॉकी इंडिया जूनियर महिला अकादमी चैंपियनशिप 2026 (जोन ए एवं बी) शुक्रवार, 24 जुलाई से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू होगा। 11 दिनों तक चलने वाला यह टूर्नामेंट 3 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश की 12 प्रमुख जूनियर महिला हॉकी अकादमियां खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी।

टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 12 टीमों को दो पूल में बांटा गया है। प्रत्येक पूल में छह-छह टीमें हैं और लीग चरण में सभी टीमें अपने-अपने पूल की अन्य टीमों से मुकाबला करेंगी। दोनों पूल से शीर्ष दो टीमें 2 अगस्त को होने वाले सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी, जबकि 3 अगस्त को तीसरे स्थान का मुकाबला और फाइनल खेला जाएगा।

पूल-ए में राजा करण हॉकी अकादमी, खालसा हॉकी अकादमी (अमृतसर), स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात-हॉकी अकादमी, हॉकी फैमिली बढ़खालसा एनसीआर हॉकी सोसायटी, तमिलनाडु हॉकी अकादमी और प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी, सोनीपत शामिल हैं।

वहीं पूल-बी में रितु रानी हॉकी अकादमी, वडीपट्टी राजा हॉकी अकादमी, भाई बेहलो हॉकी अकादमी भगता, मुंबई स्कूल्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन, अड्यार हॉकी अकादमी और मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी की टीमें खेलेंगी।टूर्नामेंट में लीग चरण के दौरान जीत पर तीन अंक, ड्रॉ पर एक अंक और हार पर कोई अंक नहीं मिलेगा। नॉकआउट मुकाबलों में बराबरी की स्थिति होने पर विजेता का फैसला अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के नियमों के अनुसार शूटआउट से किया जाएगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप टिर्की ने कहा कि जूनियर महिला अकादमी चैंपियनशिप भारत में महिला हॉकी के जमीनी ढांचे को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच बन चुकी है। इससे युवा खिलाड़ियों को देश की बेहतरीन अकादमियों के खिलाफ खेलने का अवसर मिलता है और भविष्य की राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों की पहचान करने में मदद मिलती है।

हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा कि अकादमियां युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे टूर्नामेंट खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी माहौल और राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्रदान करते हैं।

पहले दिन का कार्यक्रम

सुबह 7:30 बजे: राजा करण हॉकी अकादमी बनाम खालसा हॉकी अकादमी (अमृतसर)

सुबह 9:00 बजे: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात-हॉकी अकादमी बनाम प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी, सोनीपत

सुबह 10:30 बजे: हॉकी फैमिली बढ़खालसा एनसीआर हॉकी सोसायटी बनाम तमिलनाडु हॉकी अकादमी

दोपहर 1:30 बजे: रितु रानी हॉकी अकादमी बनाम वडीपट्टी राजा हॉकी अकादमी

दोपहर 3:00 बजे: मुंबई स्कूल्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाम अड्यार हॉकी अकादमी

शाम 4:30 बजे: भाई बेहलो हॉकी अकादमी भगता बनाम मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी।

प्रदेश स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता के ट्रायल में मंडल के 50 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

एजेंसी

मुरादाबाद। प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक फुटबाल प्रतियोगिता के लिए मंडलीय टीम ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुए। दोपहर तीन बजे से शुरू हुए ट्रायल में मंडल के करीब 50 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिला फुटबाल एसोसिएशन के सचिव मो. नासिर कमाल ने बताया कि ट्रायल के आधार पर मंडलीय टीम का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी आगामी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 8 अगस्त तक जिला खेल कार्यालय मऊ में होगा। ट्रायल में खिलाड़ियों ने टीम में जगह बनाने के लिए पूरा दमखम दिखाया। इस अवसर पर क्रीड़ाधिकारी सुनील कुमार सिंह, जिला फुटबाल संयुक्त सचिव आमिर मिर्जा, कोच सचिन बिश्नोई और फुटबाल महिला विंग की सचिव माधुरी देवी समेत अन्य मौजूद रहे।

चार महिला जूडो खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बनाई जगह, मजबूत प्रशिक्षण व्यवस्था का दिखा असर

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय जूडो को लंबे समय से जिस मजबूत खिलाड़ी विकास प्रणाली की जरूरत थी, उसका असर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगा है। बेहतर प्रशिक्षण, वैज्ञानिक तैयारी और निरंतर सहयोग के दम पर चार भारतीय महिला जूडो खिलाड़ियों ने ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में स्थान हासिल किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चुनी गई खिलाड़ियों में मध्य प्रदेश की यामिनी मौर्या, उत्तराखंड की उन्नति शर्मा, पंजाब की इशरूप नारंग और मणिपुर की तखेलंबम इनुंगनबी शामिल हैं। चारों खिलाड़ियों ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह पक्की की है। इन खिलाड़ियों को एक्सिस बैंक और इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (आईआईएस) के संयुक्त खिलाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं

मिलती रही हैं। इस पहल के माध्यम से अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को सहायता दी जा चुकी है, जिनमें 471 जूनियर और 53 एलीट महिला जूडो खिलाड़ी शामिल हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 140 से अधिक पदक जीते हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों को जापान, जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में आयोजित 11 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा लेने का अवसर मिला, जिससे उन्हें विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव प्राप्त हुआ।

एक्सिस बैंक के ग्रुप हेड विजय मुलबगल ने कहा कि खिलाड़ियों को सही माहौल और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने से उनके प्रदर्शन में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चार खिलाड़ियों का चयन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।वहीं, आईआईएस की अध्यक्ष मनीषा मल्होत्रा ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य खिलाड़ियों को केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है। भारतीय जूडो में हाल के वर्षों में उभरती नई प्रतिभाओं, विशेषकर पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के खिलाड़ियों की बढ़ती मौजूदगी यह संकेत देती है कि देश में खेल का आधार लगातार मजबूत हो रहा है। अब नजर इस बात पर होगी कि ये खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने प्रदर्शन से भारत के पदक अभियान को कितना आगे ले जा पाती हैं।

सिडनी सिक्सर्स के मुख्य कोच बने मैथ्यू मॉट, दो साल का करार

एजेंसी

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी कोच मैथ्यू मॉट को बिग बैश लीग (बीबीएल) फ्रेंचाइजी सिडनी सिक्सर्स की पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। 52 वर्षीय मॉट के साथ फ्रेंचाइजी ने दो साल का अनुबंध किया है। वह बीबीएल-16 से पहले यह जिम्मेदारी संभालेंगे। मॉट ने जेम्स होप्स की जगह ली है, जिन्होंने पिछले महीने क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन हीट के साथ दोहरी कोचिंग भूमिका स्वीकार करने के बाद पद छोड़ दिया था। मैथ्यू मॉट पिछले दो सीजन से सिडनी सिक्सर्स की पुरुष टीम के सहायक कोच थे। इसके बाद उन्होंने पिछले सीजन महिला टीम की कमान संभाली और टीम को डब्ल्यूबीबीएल चैलेंजर तक पहुंचाया। सिडनी सिक्सर्स इस सप्ताह महिला टीम के नए मुख्य कोच की घोषणा करेगी। मैथ्यू मॉट का कोचिंग करियर दो दशक से अधिक लंबा और बेहद सफल रहा है। उन्होंने 2022 से 2024 तक इंग्लैंड की पुरुष सीमित ओवर टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्य किया और जोस बटलर की कप्तानी में टीम को 2022 टी20 विश्व कप का खिताब दिलाया। इससे पहले वह 2015 से 2022 तक ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के मुख्य कोच रहे, जहां उनके मार्गदर्शन में टीम ने दो टी20 विश्व कप, 2022 महिला वनडे विश्व कप, चार एशेज सीरीज जीतीं और लगातार 26 वनडे मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। नियुक्ति के बाद मैथ्यू मॉट ने फ्रेंचाइजी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा, मैं लंबे समय से सिक्सर्स परिवार का हिस्सा रहा हूं। ऐसे में बीबीएल टीम का मुख्य कोच बनने का अवसर मिलना मेरे लिए बेहद उत्साहजनक है। यह क्लब शानदार इतिहास और विजेता संस्कृति वाला है। मैं उन मजबूत नींवों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं, जो पिछले कई वर्षों में तैयार की गई हैं। पुरुष टीम के साथ काम करते हुए मैंने खिलाड़ियों की प्रतिभा और क्षमता को करीब से देखा है। उन्होंने आगे कहा, यह जरूर निराशाजनक है कि मैं अब डब्ल्यूबीबीएल टीम का मुख्य कोच नहीं रहूंगा, लेकिन महिला टीम के साथ बिताया समय मेरे लिए बेहद खास रहा।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: भारत का पहला पदक पक्का, लवलीना सेमीफाइनल में पहुंचीं

एजेंसी

ग्लासगो । कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही भारत ने अपना पहला पदक सुनिश्चित कर लिया है। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को 'बाय' मिला है। इसके माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में पहुंचते हुए उन्होंने अपना पदक सुनिश्चित कर लिया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन 'बाय' मिलने के बाद महिलाओं के 75 किग्रा कैटेगरी के सेमीफाइनल में सीधे पहुंची। ड्रॉ में सिर्फ पांच एथलीट थे, इसलिए लवलीना समेत तीन खिलाड़ी सीधे 'अंतिम-4' (सेमीफाइनल) में पहुंच गए, जबकि बाकी दो खिलाड़ियों को एकमात्र क्वार्टरफाइनल मैच खेलना था। कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग नियमों के तहत, सेमीफाइनल में हारने वाले सभी खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है। इसका मतलब है कि ग्लासगो में अपना पहला मुकाबला खेलने से पहले ही लवलीना का कांस्य पदक पक्का हो गया है। लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल में ताफाकी के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी, जहां स्वर्ण पदक मैच में जगह बनाने का मौका होगा। जीत उन्हें फाइनल में पहुंचाएगी और कम से कम रजत पदक पक्का करेगी, जबकि हारने पर भी वह कांस्य पदक के साथ लौटेंगी। यह कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका पहला पोडियम फिनिश होगा। लवलीना गोल्ड कोस्ट 2018 में क्वार्टरफाइनल में चैंपियन बनीं सैंडी ryan से हार गई थीं और बर्मिंघम 2022 में अपना पहला ही मुकाबला हार गई थीं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बांग्लादेश को झटका, तेज गेंदबाज इबादत हुसैन बाहर

एजेंसी

नई दिल्ली। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज इबादत हुसैन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इबादत अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण बांग्लादेश में ही रहेंगे और टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं करेंगे।

बांग्लादेश की टीम 13 अगस्त से डार्विन में शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 चक्र का हिस्सा है। फिलहाल बांग्लादेश डब्ल्यूटीसी अंकतालिका में चौथे स्थान पर है और इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा। हालांकि इबादत की गैरमौजूदगी के बीच टीम को एक राहत भी मिली है।

तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने ऑस्ट्रेलिया दौरे की बेहतर तैयारी के लिए श्रीलंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) से अपना नाम वापस ले लिया है। तस्कीन ने कहा, मेरा मुख्य लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी करना है। हमने जिम्बाब्वे में लगातार छह मैच खेले हैं। अगर मैं एलपीएल भी

खेलता और फिर सीधे ऑस्ट्रेलिया जाता तो टेस्ट मैच की तैयारी प्रभावित होती। इसलिए थोड़ा नुकसान उठाकर भी मैंने एलपीएल से हटने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया जैसी टेस्ट सीरीज बार-बार नहीं आती।

नाहिद राणा और लिटन दास की फिटनेस पर नजर

बांग्लादेश के लिए एक और चिंता तेज गेंदबाज नाहिद राणा की फिटनेस है। उनके शरीर के साइड हिस्से में लगी चोट की स्कैन रिपोर्ट का टीम प्रबंधन को इंतजार है। वहीं अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास भी पिंडली (काफ) की चोट से उबर रहे हैं और टीम को उम्मीद है कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उपलब्ध रहेंगे।

बांग्लादेश की टीम अगले महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी, जहां 3 अगस्त से डार्विन में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी।

बल्लेबाजों पर जताया भरोसा

बांग्लादेश के बल्लेबाजी कोच मोहम्मद अशरफुल ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट में मिली बड़ी हार के बावजूद अपने बल्लेबाजों पर भरोसा जताया है।

अशरफुल ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में चुनौती कठिन होगी, लेकिन सकारात्मक बात यह है कि हम 10-12 दिन पहले वहां पहुंचेंगे और अभ्यास मैच खेलने का मौका मिलेगा। यदि सभी खिलाड़ी फिट रहे तो हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सार्वजनिकवित्तउन्होंने कहा, पिछले सात महीनों में हमारे बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। एक सीरीज या एक टेस्ट खराब होने का मतलब यह नहीं कि हम निराश हो जाएं। अलग-अलग परिस्थितियों में खेलने से खिलाड़ियों को अनुभव मिला है और हमें विश्वास है कि वे ऑस्ट्रेलिया में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

सीरीज का कार्यक्रम

पहला टेस्ट: 13-17 अगस्त, डार्विन

दूसरा टेस्ट: 22-26 अगस्त, मैके

नेपाल को भारत-बांग्लादेश से साल भर में बिजली निर्यात से 18.76 अरब का शुद्ध लाभ

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने पिछले वित्तीय वर्ष में पहली बार पूरे 12 महीनों तक बिजली का निर्यात किया। इस दौरान नेपाल ने 29 अरब 32 करोड़ 47 लाख रुपये की बिजली भारत और बांग्लादेश को निर्यात की। आयात पर केवल 10 अरब 56 करोड़ रुपये खर्च हुए। इससे नेपाल को 18 अरब 76 करोड़ 50 लाख रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। घरेलू बिजली उत्पादन में वृद्धि और मार्च-अप्रैल के दौरान भी अच्छी वर्षा होने से भारत और बांग्लादेश को बिजली निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, जबकि भारत से बिजली आयात में कमी दर्ज की गई। प्राधिकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024/25 में बिजली व्यापार से केवल 4 अरब 54 करोड़ 80 लाख रुपये का व्यापार अधिशेष था, जो पिछले वर्ष 2025/26 में लगभग चार गुना बढ़ गया। बीते वित्तीय वर्ष में नेपाल ने भारत और बांग्लादेश को कुल 3 अरब

87 करोड़ 74 लाख 92 हजार यूनिट बिजली निर्यात कर 29 अरब 32 करोड़ 47 लाख 43 हजार रुपये की आय अर्जित की। यह आय वित्तीय वर्ष 2081/82 में हुई 17 अरब 47 करोड़ 10 लाख रुपये की कमाई की तुलना में 67.84 प्रतिशत अधिक है। इतिहास नेपाल विद्युत प्राधिकरण वर्तमान में वर्षा ऋतु के दौरान भारत को 1,000 मेगावाट से अधिक और बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात कर रहा है। नेपाल की अधिकांश जलविद्युत परियोजनाएं 'रन-ऑफ-द-रिवर' (आरओआर) प्रणाली पर आधारित हैं। पहले सामान्यतः मई के अंत से दिसंबर के पहले सप्ताह तक ही बिजली निर्यात संभव हो पाता था। लेकिन पिछले वर्ष चैत और बैसाख जैसे ऑफ-सीजन में भी अच्छी वर्षा होने से बिजली उत्पादन बढ़ा और नेपाल पूरे वर्ष बिजली निर्यात करने में सफल रहा। प्राधिकरण के प्रवक्ता राजन ढकाल के अनुसार, नेपाल में हर वर्ष 500 से 600 मेगावाट नई बिजली उत्पादन क्षमता जुड़ रही है। घरेलू खपत के बाद बची हुई बिजली का निर्यात लगातार बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में भी यह रुझान जारी रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, नेपाल में घरेलू आवश्यकता पूरी करने के बाद बची हुई बिजली का निर्यात किया जाता है। हर वर्ष 500 से 600 मेगावाट नई क्षमता जुड़ने से निर्यात बढ़ा है और इसके साथ ही निर्यात से होने वाली आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है। नेपाल की अधिकांश जलविद्युत परियोजनाएं नदी प्रवाह पर आधारित हैं। मानसून के दौरान नदियों में जलस्तर बढ़ने से बिजली उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसी अवधि में बिजली निर्यात भी सबसे ज्यादा होता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में दो महीने के टॉप लेवल पर क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड 95.38 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंचा

एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे तनाव और खाड़ी देशों से कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग और तेज होने की आशंका के बीच ब्रेंट क्रूड आज दो महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। आज ब्रेंट क्रूड ने तेजी दिखाते हुए 95 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर लिया। इसी तरह वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड भी आज 88 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ने आज 0.45 डॉलर प्रति बैरल की मामूली उछाल के साथ 91.46 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। ट्रेडिंग शुरू होने के बाद इसकी कीमत उछल कर 95.38 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले दो महीने के दौरान ब्रेंट क्रूड का ये सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि दिन के कारोबार में इसकी कीमत में मामूली गिरावट भी आई। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 3.61 डॉलर प्रति बैरल यानी 3.97 प्रतिशत की तेजी के साथ 94.62 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड ने आज सिर्फ 0.15 डॉलर प्रति बैरल की सामान्य बढ़त के साथ 84.59 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से आज के कारोबार की शुरुआत की। थोड़ी देर बाद ही डब्ल्यूटीआई क्रूड उछल कर 88.61 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया।

बीपीसीएल को पहली तिमाही में 3,962 करोड़ रुपये का घाटा

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की (अप्रैल-जून) पहली तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया है। कंपनी को अप्रैल-जून तिमाही में 3962.13 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है। बीपीसीएल ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें लागत से कम रखने की वजह से वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी को ये घाटा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 3,333.97 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा कि एलपीजी पर कंपनी को जून तिमाही में 3,485.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसके अलावा मार्च, 2026 तक 12,318.52 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी बकाया है। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी की परिचालन आय बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 1.35 लाख करोड़ रुपये थी।

नेस्ले इंडिया को पहली तिमाही का शुद्ध लाभ 958.68 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। दैनिक उपभोग की वस्तुएं बनाने वाली प्रमुख कंपनी नेस्ले इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 की (अप्रैल-जून) पहली तिमाही के अपने नतीजे का ऐलान कर दिया है। नेस्ले इंडिया का अप्रैल-जून में एकीकृत शुद्ध लाभ (मुनाफा) 48.26 फीसदी बढ़कर 958.68 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 646.59 करोड़ रुपये था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में उत्पादों की बिक्री से नेस्ले इंडिया का राजस्व 25.4 फीसदी बढ़कर 6,363.27 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 5073.96 करोड़ रुपये था। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) मनीष तिवारी ने कहा, ''हमने मात्रा वृद्धि के दम पर बिक्री में 25.4 फीसदी वृद्धि के साथ मजबूत तिमाही प्रदर्शन किया। बिक्री 6,363.3 करोड़ रुपये रही, जिसे हमारे ब्रांडों पर उपभोक्ताओं के निरंतर भरोसे और प्रभावी क्रियान्वयन का समर्थन मिला। वहीं, भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद निर्यात में 35.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में नेस्ले इंडिया की कुल आय 25.5 फीसदी बढ़कर 6,400.65 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 5,100.33 करोड़ रुपये थी। कंपनी का कुल खर्च 20.71 फीसदी बढ़कर 5,070.03 करोड़ रुपये रहा।

अबतक 3 करोड़ से ज्यादा करदाताओं ने दाखिल किया रिटर्न

नई दिल्ली। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अब तक तीन करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल किए जा चुके हैं, जिनमें से अकेले 21 जुलाई को 15 लाख से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने बताया कि आकलन वर्ष 2026-27 के लिए पहले ही 3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं, जबकि अकेले मंगलवार, 21 जुलाई को ही 15 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइल किए गए हैं। डेडलाइन के समय होने वाली भीड़-भाड़ का इंतजार न करें। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अपना आईटीआर-1 और आईटीआर-2, 31 जुलाई 2026 से पहले http://incometa&.gov.in पर फाइल करें। उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई की डेडलाइन उन लोगों के लिए है, जिन्हें आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फाइल करना है। आमतौर पर अगर आपकी सालाना आय इनकम टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा है, तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है। क्यूब हाइवेज ट्रस्ट का आईपीओ लॉन्च, 3 अगस्त को हो सकती है लिस्टिंग

क्यूब हाइवेज ट्रस्ट का आईपीओ लॉन्च, 3 अगस्त को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए काम करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्यूब हाइवेज ट्रस्ट इन्विट का 5,000 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 24 जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 29 जुलाई को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 30 जुलाई को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर तीन अगस्त को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। पहले दिन दोपहर एक बजे तक ये आईपीओ सिर्फ दो प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 151 रुपये से लेकर 152 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 95 शेयर का है। आईपीओ के तहत कुल 32,89,47,368 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे जा रहे हैं। आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) को अधिकतम 75 प्रतिशत शेयर अलॉट किए जाएंगे, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) को न्यूनतम 25 प्रतिशत शेयर दिए जाएंगे। इस इश्यू के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। क्यूब हाइवेज ट्रस्ट इन्विट की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी को 999.57 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ कर 1,422.89 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

उतार-चढ़ाव के बीच शेयर बाजार में रिकवरी का रुख, शुरुआती दबाव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी की स्थिति सुधरी

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार आज शुरुआती कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव के बीच रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। आज के कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। बाजार खुलने के तुरंत बाद लिवालों और बिकवालों के बीच खींचतान शुरू हो गई, जिसकी वजह से बाजार की चाल में उतार-चढ़ाव होने लगा। इस उतार-चढ़ाव के बीच पहले एक घंटे के कारोबार में खरीदारों का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। शुरुआती एक घंटे का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 0.18 प्रतिशत और निफ्टी 0.17 प्रतिशत की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। पहले एक घंटे का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट की दिग्गज कंपनियों में से श्रीराम फाइनेंस, एटरनल, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ट्रेंट लिमिटेड और बजाज फिनसर्व के शेयर 1.29 प्रतिशत से लेकर 0.61 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेट्रीज, नेस्ले, अदानी एंटरप्राइजेज, टाटा स्टील और अदानी पोर्ट्स के शेयर 2.83 प्रतिशत से लेकर 0.80 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,639 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 957 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 1,682 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 10 शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे। दूसरी ओर, 20 शेयर बिकवाली के दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 18 शेयर हरे निशान में और 32 शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे थे। बीएसई का सेंसेक्स आज 239.95 अंक यानी 0.31 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 76,515.10 अंक के स्तर पर खुला। बाजार खुलते ही लिवालों और बिकवालों के बीच एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल में उतार-चढ़ाव होने लगा। बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स 400 अंक से अधिक टूट कर 76,344.67 अंक के स्तर तक गिर गया। हालांकि पहले 20 मिनट के बाद ही बाजार में खरीदारों का जोर बढ़ता हुआ नजर आने लगा, जिससे इस सूचकांक की चाल में सुधार होने लगा। बाजार में लगातार जारी खरीद बिक्री के बीच शुरुआती एक घंटे का कारोबार होने के बाद सुबह 10:15 बजे सेंसेक्स 140.05 अंक की कमजोरी के साथ 76,615 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

सर्राफा बाजार में चमका सोना, चांदी का भी बढ़ा भाव

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। भाव में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 2,100 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 2,190 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। वहीं चांदी के भाव में भी आज 5,200 रुपये प्रति किलोग्राम की जोरदार तेजी नजर आ रही है।

भाव में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,46,420 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,46,570 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,34,310 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,34,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 2,40,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,46,570 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,460 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक

राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,46,420 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,34,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,46,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,360 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,46,420 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,34,310 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,46,420 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,34,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,470 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,34,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,46,570 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,34,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,470 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,34,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,46,570 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,34,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

आईटीसी का 2035 तक आठ लाख करोड़ रुपये के एफएमसीजी बाजार का लक्ष्य

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनी आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजीव पुरी ने गुरुवार को कहा कि कंपनी ने 2035 तक अपने पैकेज्ड गुड्स व्यवसाय के लिए 8 लाख करोड़ रुपये के एड्रेसेबल मार्केट (कुल संभावित बाजार) का लक्ष्य रखा है। कंपनी ब्रांड निर्माण, डिजिटल वाणिज्य के विस्तार और रणनीतिक अधिग्रहणों के जरिये अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान दे रही है।

आईटीसी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि भारतीय एफएमसीजी बाजार 'उल्लेखनीय विस्तार' के लिए तैयार है, देश का उपभोक्ता परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। उन्होंने बताया कि कंपनी इस विशाल अवसर को भुनाने के लिए ब्रांड-बिल्डिंग, एआई-संचालित उपभोक्ता अंतर्दृष्टि, डिजिटल कॉमर्स और रणनीतिक अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित कर रही

है। पुरी ने कहा कि आकांक्षी भारत का उदय, प्रीमीयमीकरण, जेन-जेड और जेन-अल्फा उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या, डिजिटल पहुंच का विस्तार और त्वरित वाणिज्य (क्विक कॉमर्स) का बढ़ता चलन उत्पाद श्रेणियों, वितरण माध्यमों और उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन रुझानों का लाभ उठाने के लिए आईटीसी कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित उपभोक्ता अंतर्दृष्टि प्रणाली का उपयोग कर रही है, जिससे सूक्ष्म स्तर पर उपभोक्ताओं का वर्गीकरण संभव हो रहा है और उनकी बदलती जरूरतों, जीवनशैली तथा उपभोग के अवसरों के अनुरूप अलग-अलग उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं। पुरी ने कहा कि वर्ष 2035 तक कंपनी का लक्षित बाजार लगभग आठ लाख करोड़ रुपये का होने का अनुमान है, जो वृद्धि की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। भारत का उपभोक्ता परिदृश्य भी तेजी से बदल रहा है। पुरी ने कहा कि आईटीसी के दैनिक उपभोग की वस्तुओं (एफएमसीजी) कारोबार ने मजबूत वृद्धि बनाए रखी है। उन्होंने बताया कि कंपनी के पास अब 30 से अधिक विश्वस्तरीय एफएमसीजी ब्रांड हैं। इनसे प्राप्त राजस्व वित्त वर्ष 2020-21 के लगभग 14,720 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 24,200 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। साथ ही लाभप्रदता में भी लगातार सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि एफएमसीजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी बनने की हमारी आकांक्षा इसी व्यापक दृष्टि पर आधारित है।

नवीनीकरण शुल्क न देने पर 34 निवेश सलाहकारों के पंजीकरण रद्द

एजेंसी

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने पर 34 निवेश सलाहकारों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 21 जुलाई के जारी आदेश में कहा कि शुल्क का भुगतान न होने के कारण इन निवेश सलाहकारों का पंजीकरण स्वतः प्रभावी नहीं रहा और तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है सेबी ने जांच में पाया कि 34 सलाहकारों ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर ये शुल्क जमा नहीं किया। इसके बाद सेबी ने जून में इन संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पूंजी बाजार नियामक सेबी (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013 के तहत पंजीकृत निवेश सलाहकारों को हर 5 साल में अपना पंजीकरण जारी रखने के लिए नवीनीकरण शुल्क देना अनिवार्य होता है। इस फैसले से प्रभावित होने वाले निवेश सलाहकारों में ऐश्वा फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एल्गो सिस्टम्स,

कैंडीफ्लॉस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, कैपिटलविया ग्लोबल रिसर्च लिमिटेड, प्रॉस्पर रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, द जीआरएस सॉल्यूशन और ट्रेडक्योर फाइनेंशियल रिसर्च शामिल हैं। एक अलग आदेश में सेबी ने 11 शोध विश्लेषकों के पंजीकरण भी रद्द कर दिए हैं। पंजीकृत शोध विश्लेषक को भी हर पांच साल में नवीनीकरण शुल्क देना होता है।

सोटेफिन भारत ने निवेशकों को किया खुश, प्रीमियम लिस्टिंग के बाद लगा अपर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली। ऑटोमेटेड कार पार्किंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी सोटेफिन भारत के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूती के साथ एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 187 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 9.63 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 205 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली के सपोर्ट से ये शेयर थोड़ी देर में ही उछल कर 215.25 रुपये के अपर सर्किट लेवल तक पहुंच गया। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 28.25 रुपये यानी 15.11 प्रतिशत का फायदा हो गया। इस कंपनी का 89.76 करोड़ रुपये का आईपीओ 16 से 20 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 3.99 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 2.82 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 6.05 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 3.78 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 48 लाख नए शेयर बेचे गए हैं। आईपीओ में शेयरों की बिक्री से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी कोलकाता में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने, नए ऑफिस के परिसर को विकसित करने, पुराने कर्ज के बोझ को कम करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। सोटेफिन भारत की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत में लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 6.25 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 11.31 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 17.37 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 56.87 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 94.15 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को कुल 118.23 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज के बोझ में उतार-चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी पर 18.78 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में कम होकर 12.16 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

एचडीएफसी बैंक का बाजार मूल्यांकन एक लाख करोड़ रुपये घटा

एजेंसी

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक के शेयर में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई। इसके साथ बैंक का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) एक लाख करोड़ रुपये कम हो गया है। पिछले तीन दिनों में मार्जिन को लेकर चिंता के कारण बैंक का शेयर आठ फीसदी से अधिक टूट गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में बैंक का शेयर 1.09 फीसदी टूटकर 753.15 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय इसमें 1.47 फीसदी तक की गिरावट आई और यह 750.25 रुपये पर आ गया था। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में यह एक फीसदी की गिरावट के साथ 753.15 रुपये पर बंद हुआ। शेयर बाजार के जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन दिन में बैंक के शेयर में 8.11 फीसदी की गिरावट आई है, जिससे बाजार

मूल्यांकन 1 लाख करोड़ रुपये कम होकर 11,59,950.98 करोड़ रुपये पर आ गया। इसके साथ ही कंपनी बाजार पूंजीकरण के लिहाज से रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आ गई। भारती एयरटेल 12,16,839.14 करोड़ रुपये के बाजार मूल्यांकन के साथ दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 17,44,141.25 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है। उल्लेखनीय है कि एचडीएफसी बैंक का एकल आधार पर शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 202627 की अप्रैल-जून तिमाही में पांच फीसदी बढ़कर 19,059.72 करोड़ रुपये रहा है। बैंक का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि में 18,155.21 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि, पहली तिमाही में बैंक की कुल आय घटकर 92,184 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की इसी तिमाही में 99,200 करोड़ रुपये थी।

गुजरात के अंकलेश्वर में मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्टरी का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने गुजरात के अंकलेश्वर में मेफेड्रोन बनाने वाली एक फैक्टरी का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। डीआईआई ने मौके से 21 लाख रुपये भी बरामद किए हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक बड़े अभियान में डीआरआई के अधिकारियों ने अंकलेश्वर में एक आवासीय परिसर से संचालित हो रही एक गुप्त मेफेड्रोन निर्माण फैक्टरी का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है। इस दौरान मादक पदार्थों के निर्माण और तस्करी नेटवर्क में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक खुफिया जानकारी पर आधारित इस अभियान में डीआरआई अधिकारियों ने एक अत्याधुनिक निर्माण उपकरणों से सुसज्जित कार्यरत प्रयोगशाला का पता लगाया, जिसमें एक औद्योगिक ओवन ड्रायर, हॉट प्लेट हीटर, कंडेंसर असेंबली, इलेक्ट्रिक स्टिरर और मेफेड्रोन के गुप्त निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य प्रयोगशाला उपकरण शामिल थे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक डीआरआई के अधिकारियों की तलाशी के बाद 1.349 किलोग्राम मेफेड्रोन ठोस रूप में, 6.825 किलो 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन और 120 लीटर मोनोमिथाइलमाइन के साथ 60 किलो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, 40 लीटर टोल्यून और मिश्रित अम्लों वाले दो कंटेनर बरामद किए गए।

ट्रंप का दावा: वैश्विक निवेश के 19.2 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की ओर आ रहे, इसे बताया 'स्वर्णिम युग'

एजेंसी

वॉशिंगटन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने अमेरिका के लिए 19.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी व्यापार और आर्थिक नीतियों के कारण एशिया और यूरोप की कई विनिर्माण कंपनियां अपना उत्पादन अमेरिका स्थानांतरित कर रही हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (ग्लोबल सप्लाई चेन) का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (स्थानीय समयानुसार) जॉर्जिया के मैरिएटा में आयोजित एक रैली में दावा किया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 'स्वर्णिम युग' में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने नए विनिर्माण संयंत्रों, दवा उद्योग में निवेश और ऊर्जा साझेदारियों का हवाला देते हुए कहा कि एशिया और यूरोप की कई कंपनियां अब अन्य देशों के बजाय अमेरिका में निवेश और उत्पादन को प्राथमिकता दे रही हैं। ट्रंप ने कहा, 'मेरे प्रशासन के दो साल पूरे होने से पहले ही, बल्कि पहले साल के अंत तक ही, हमने दुनिया भर से 19.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के नए निवेश सुनिश्चित किए हैं।' उन्होंने पूर्ववर्ती प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा, 'चार वर्षों में उन्होंने 1 ट्रिलियन डॉलर से भी कम निवेश हासिल किया, जबकि हमने केवल 15 महीनों में 19.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया है।' ट्रंप ने दावा किया कि कई वैश्विक कंपनियां अपना उत्पादन अमेरिका में स्थानांतरित कर रही हैं।

उन्होंने कहा, 'टोयोटा ने अभी घोषणा की है कि वह मेक्सिको छोड़कर अमेरिका आ रही है और यहां दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र बनाएगी। वे सभी वापस आ रहे हैं। वे कनाडा और मेक्सिको छोड़ रहे हैं। जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया से भी कंपनियां अमेरिका आ रही हैं।'

राष्ट्रपति ने जॉर्जिया में घोषित नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दवा कंपनी यूसीबी (ष्ठक्क) 2 अरब डॉलर का निवेश कर ग्विनेट, जॉर्जिया में अपना पहला अमेरिकी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी।

उन्होंने यह भी बताया कि जापान जॉर्जिया में 60 करोड़ डॉलर की लागत से हीरा प्रसंस्करण (डायमंड प्रोसेसिंग) इकाई स्थापित कर रहा है, जबकि यामाहा मोटर केनेसॉ में अपना नया अमेरिकी मुख्यालय बना रही है। रोजगार के मोर्चे पर ट्रंप ने दावा किया, 'आज अमेरिका में पहले से कहीं अधिक लोग रोजगार में हैं और यह अंतर बहुत बड़ा है।' उन्होंने शेयर बाजार और महंगाई का जिक्र करते हुए कहा, 'चुनाव के बाद से शेयर बाजार 73 बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। जहां शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर है, वहीं महंगाई लगातार घट रही है।' ट्रंप ने अपनी सरकार की कर नीतियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हाल ही में लागू किए गए कानून के तहत टिप (बख्शीश), ओवरटाइम वेतन और कई अमेरिकियों के लिए सोशल सिक्योरिटी लाभ पर कर समाप्त कर दिया गया है। उनके अनुसार, जॉर्जिया में 1.30 लाख टिप पाने वाले कर्मचारियों ने औसतन 7,000 डॉलर से अधिक कर की बचत की है, जबकि लगभग 7 लाख कर्मचारियों को 'ओवरटाइम पर कोई टैक्स नहीं' प्रावधान का लाभ मिला है। ट्रंप ने बच्चों के लिए शुरू किए गए 'ट्रंप अकाउंट्स' का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे कर लाभ वाले बचत खातों की योजना बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देना है। ऊर्जा क्षेत्र पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा, 'हम उस अभियान की लागत कई बार वसूल कर चुके हैं। हम भारी मात्रा में तेल प्राप्त कर रहे हैं। यदि अमेरिका और वेनेजुएला को मिलाकर देखें तो हमारे पास दुनिया के लगभग 62 प्रतिशत तेल संसाधन हैं।' ट्रंप ने दावा किया कि उनकी आर्थिक रणनीति के कारण अमेरिकी उद्योग फिर से प्रतिस्पर्धी बन रहा है और कंपनियां विदेशों में उत्पादन करने के बजाय अमेरिका में ही विनिर्माण कर रही हैं।

लावरोव और रूबियो की मुलाकात, यूक्रेन संघर्ष के समाधान पर हुई बात

एजेंसी
मनीला । रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को मनीला में आयोजित आसियान मंत्रिस्तरीय बैठकों के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस बैठक में यूक्रेन संघर्ष सुलझाने को लेकर मास्को तत्पर दिखा और 'एंकोरेज फॉर्मूले' को लेकर प्रतिबद्धता जताई। रूसी मीडिया के अनुसार, लावरोव ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए मास्को तैयार है और एंकोरेज में हुई सहमति को लेकर प्रतिबद्धता बनाए रखता है। उन्होंने रूबियो को युद्ध क्षेत्र की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी और यूक्रेन को आगे हथियारों की आपूर्ति नहीं करने के महत्व पर जोर दिया। रूस के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि दोनों नेताओं ने रूस और अमेरिका के राजनयिक मिशनों के कामकाज को सामान्य बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा की। इसके अलावा

पश्चिम एशिया की स्थिति सहित कई क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

रूसी समाचार एजेंसी टीएएसएस के अनुसार, दोनों विदेश मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि विदेश मंत्रालयों के बीच संपर्क जारी रखा जाएगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मंच भी शामिल हैं। बैठक में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले 26 जून में लावरोव ने यूक्रेन संकट के समाधान में अमेरिका की भूमिका को लेकर स्पष्टता की मांग की थी। यह बयान मार्को रूबियो की उन टिप्पणियों के बाद आया था, जिनमें उन्होंने एंकोरेज शिखर बैठक के परिणामों पर चर्चा की थी। रूबियो ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एंकोरेज बैठक में यूक्रेन मुद्दे पर कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ था। राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप अगस्त 2025 में एंकोरेज में मिले थे और दोनों ने यूक्रेन संघर्ष को लेकर चर्चा की थी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए लावरोव ने कहा था, 'एंकोरेज में हुई बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, मार्को रूबियो और मैं खुद मौजूद था, पुतिन ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से एक-एक कर अमेरिकी प्रस्तावों की पुष्टि की थी। पुतिन ने हर बिंदु के बाद विटकॉफ से पूछा था कि क्या उन्होंने मॉस्को यात्रा के दौरान दिए गए अमेरिकी विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत किया है।' लावरोव के मुताबिक, विटकॉफ ने हर बार हां कहकर इसकी पुष्टि की थी। रूसी विदेश मंत्री ने आगे कहा, 'जब रूबियो यह कहते हैं कि अलास्का (एंकोरेज) में केवल प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कोई समझौता नहीं हुआ, तो यह सवाल उठता है कि समझौते का अर्थ क्या है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने मनीला में श्रीलंकाई, बांग्लादेशी समकक्षों और ईयू की काजा कैलास से की मुलाकात

एजेंसी
मनीला । भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आसियान समिट में शामिल होने के लिए फिलीपींस के मनीला पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कैलास से मुलाकात की। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने अपने श्रीलंकाई और बांग्लादेशी समकक्ष विजिथा हेराथ और खलीलुर रहमान से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने श्रीलंका और बांग्लादेश के अपने समकक्षों के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'एआरएफ मीटिंग के दौरान श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेराथ और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मिलकर खुशी हुई।' वहीं एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'ईयू की एचआरवीपी काजा कैलास से मिलकर अच्छा लगा।' विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 22-23 जुलाई 2026 को मनीला, फिलीपींस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आसियान फ्रेमवर्क के तहत विदेश मंत्री लेवल की मीटिंग्स में हिस्सा लिया। इन बैठकों में आसियान-इंडिया, ईस्ट एशिया समिट (ईएएस) और आसियान रीजनल फोरम (एआरएफ) मीटिंग्स शामिल है।

बता दें, आसियान से इतर, विदेश मंत्री ने फिलीपींस की विदेश मंत्री मा. थेरेसा पी. लाजारो, ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष सीनेटर पेनी वोंग, चीनी समकक्ष वांग यी, अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियान बालाकृष्णन, कनाडाई समकक्ष अनिता आनंद, थाईलैंड के सिहासक फुआंगकेटकेओ, न्यूजीलैंड के विंस्टन पीटर्स और आसियान के सेक्रेटरी जनरल डॉ. काओ किम होर्न से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री जयशंकर ने इन नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकों में की।

ईरान समझौते के लिए अभी तैयार नहीं पर जल्द ही तैयार हो जाएगा : ट्रंप

एजेंसी
वॉशिंगटन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारी सैन्य दबाव झेलने के बावजूद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता करने के लिए अभी तैयार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि तेहरान लगातार बातचीत के दौरान अपना रुख बदलता रहा, जबकि अमेरिका अपने इस संकल्प पर कायम है कि वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ईरान के साथ संघर्ष में मारे गए चार अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (स्थानीय समयानुसार) जॉर्जिया में एक चुनावी रैली जैसी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तेहरान के प्रति अपनी सरकार की सैन्य और कूटनीतिक नीति का बचाव किया और इस टकराव को दुनिया में अमेरिका की ताकत बहाल करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बताया। ट्रंप ने कहा, 'शेयर बाजार लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। मैं ईरान के इस टकराव को एक छोटी झड़प कहता हूं। इसके बावजूद चुनाव के बाद से शेयर बाजार 73 बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है।' उन्होंने इस सैन्य तनाव को अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था और निवेशकों के भरोसे से जोड़कर पेश किया। ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि तेहरान अभी भी किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है।

नाइजीरिया में स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में हैजा का प्रकोप, बोर्नी राज्य में 200 लोगों की मौत

वाशिंगटन। स्वच्छ पानी और पर्याप्त सफाई व स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में नाइजीरिया के पूर्वोत्तर राज्य बोर्नो में पिछले दो महीनों में हैजा के प्रकोप में लगभग 200 लोगों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी एक अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा मानवीय संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडिसिन्स सैन्स फ्रंटियर्स-एमएसएफ भी कहते हैं) ने दी है। बुधवार को स्थानीय समयानुसार जारी एक बयान में एमएसएफ ने बीमारी के बढ़ते प्रकोप पर चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी कि चल रहे राहत प्रयासों के बावजूद यह बीमारी स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं पर भारी पड़ सकती है। एमएसएफ ने बोर्नो राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 12 जुलाई तक राज्य में कम से कम 198 लोगों की मौत हो चुकी थी और 35,500 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए थे। संगठन ने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों और मानवीय सहायता भागीदारों के साथ मिलकर काम करते हुए उसने 12 जुलाई तक हैजा के संदिग्ध 24,000 से अधिक रोगियों का इलाज किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, संगठन ने प्रभावित समुदायों में स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्त उपलब्धता को बीमारी के लगातार फैलने का कारण बताया।

सोने की खदान में हादसा, सुरंग ढहने से पांच खनिकों की मौत, कई के फंसे होने की आशंका

नारोक (केन्या)। दक्षिण-पश्चिमी केन्या के नारोक काउंटी में एक सोने की खदान ढहने से कम से कम पांच खनिकों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने मृतकों की पुष्टि भी की। नारोक काउंटी के पुलिस कमांडर पैट्रिक लोबोलिया ने बताया कि भारी बारिश के बाद सुरंग ढह गई, जिसके कारण कुछ खनिकों के अंदर फंसे होने की आशंका है। उन्हें बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। लोबोलिया ने एजेंसी को फोन पर बताया, 'बचाव दल मौके पर मौजूद है और उन लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके अभी भी अंदर फंसे होने की संभावना है।' उन्होंने कहा कि किलिमापेसा इलाके में तलाशी और बचाव का काम जारी है, लेकिन विशेष खनन उपकरणों की कमी के कारण इसमें परेशानी आ रही है। लोबोलिया ने बताया, 'विशेष भूमिगत खोज उपकरणों और कैमरों की कमी के कारण बचाव अभियान धीमी गति से चल रहा है। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और इलाज के लिए पास के स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा गया है।' किलिमापेसा, नारोक शहर से करीब 180 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और यहां केन्या की सबसे बड़ी व्यावसायिक सोने की खदान है। यह घटना केन्या के सोना खनन क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई है। पिछले कुछ वर्षों में यहां खदानों में हुए हादसों में कई लोगों की मौत हो चुकी है।

जॉर्डन के अमेरिकी एयर बेस पर हमले में भारतीय मूल की अमेरिकी सार्जेंट लापता, मौत की आशंका

न्यूयॉर्क। अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) के मुताबिक, भारतीय मूल की अमेरिकी सैनिक एंजेला रामप्रसाद के जॉर्डन में एक सैन्य अड्डे पर हुए ईरानी हमले में मारे जाने की आशंका है। 25 साल की आर्मी सार्जेंट एंजेला रामप्रसाद के बारे में विभाग ने कहा कि माना जा रहा है कि 17 जुलाई 2026 को जॉर्डन के मुवफ्फक साल्टी एयर बेस पर दुश्मन के हमले के दौरान उनकी मौत हो गई। विभाग ने कहा कि इस घटना की जांच अभी जारी है। पहले उन्हें लापता बताया गया था। बाद में उनकी आधिकारिक स्थिति बदलकर 'ड्यूटी स्टेटस-ठिकाना अज्ञात' कर दी गई और अब माना जा रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है। एंजेला भारतीय मूल के उस समुदाय से थीं, जिसके लोग गुयाना से अमेरिका जाकर बसे हैं। स्थानीय डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नेता के मुताबिक, उनके पिता का नाम बासदेव रामप्रसाद है। पेंटागन ने बताया कि एंजेला न्यूयॉर्क सिटी के क्वींस इलाके के ओजोन पार्क की रहने वाली थीं। इस इलाके में भारतीय मूल के गुयाना से आए लोगों की बड़ी आबादी रहती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पेसाच ओसिना ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वह 'हर उस इंसान के लिए एक अनमोल तोहफा थीं जो उन्हें जानता था।'

भारी बारिश और फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, खैबर पख्तूनख्वा में 18 की मौत

एजेंसी
इस्लामाबाद । पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड ने बड़े स्तर पर तबाही मचाई है। खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत में 19 जुलाई से अब तक बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई जबकि 19 अन्य घायल हुए हैं। यह जानकारी प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) ने गुरुवार को दी। पीडीएमए के अनुसार, अधिकांश मौत मकानों की छत या दीवार गिरने और लोगों के फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से हुई। मृतकों में आठ बच्चे, सात पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। वहीं, घायलों में 11 पुरुष, चार महिलाएं और चार बच्चे हैं। बारिश और बाढ़ से 30 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 23 आंशिक रूप से और सात पूरी तरह से नष्ट हो गए।

बारिश से जुड़ी घटनाएं बुनैर, स्वाबी, मर्दान, बाजौर, शांगला, लोअर चितराल, पेशावर, नौशेरा, खैबर, लोअर और अपर दीर, एबटाबाद, मानसेहरा, तोर घर, कुर्रम तथा उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान सहित कई जिलों में दर्ज की गई हैं। पीडीएमए ने बताया

कि रेस्क्यू 1122, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान जारी है। उधर, पंजाब प्रांत के गुजरांवाला, नारोवाल, पाकपत्तन और लाहौर में भी बारिश से जुड़ी घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हुए हैं। सबसे अधिक प्रभावित गुजरांवाला रहा, जहां मकानों की छत और दीवार गिरने, तालाबों में डूबने और करंट लगने जैसी घटनाओं में छह लोगों, जिनमें अधिकांश बच्चे थे, की जान चली गई। वहीं, पाकपत्तन में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई और उनकी मां घायल हो गईं। लाहौर के गुलशन-ए-रावी इलाके में एक फैक्ट्री की छत गिरने से चार मजदूर घायल हो गए। इसके अलावा गुजरात में जीटी रोड बाईपास पर बारिश के कारण फिसलकर एक ट्रेलर खाई में गिर गया। लगातार लगभग 10 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण गुजरात और गुजरांवाला के मुख्य मार्ग और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए, जिससे व्यापारिक गतिविधियां और दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

शलामचेह बॉर्डर क्रॉसिंग पर अमेरिका ने बरसाए बम

एजेंस
तेहरान/बगदाद । अमेरिका ने लगातार 12वीं रात ईरान के कई शहरों और इलाकों पर बम बरसाए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने इसकी तस्दीक भी की। इन हमलों के बाद शलामचेह बॉर्डर क्रॉसिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। ईरानी मीडिया ने इस क्रॉसिंग पर दो लोगों की मौत और 11 के घायल होने की पुष्टि की। शलामचेह बॉर्डर आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ईरान और इराक को जोड़ने वाला शलामचेह बॉर्डर क्रॉसिंग दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सीमा मार्गों में से एक है। व्यावसायिक, धार्मिक और सामरिक रूप से भी यह काफी अहम माना जाता है। यह न केवल द्विपक्षीय व्यापार का प्रमुख गलियारा है, बल्कि इराक के पवित्र शिया धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है।

शलामचेह बॉर्डर दक्षिणी इराक को ईरान से जोड़ता है और दोनों देशों के बीच वस्तुओं के आयात-निर्यात तथा लोगों की आवाजाही के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन हजारों यात्री और व्यापारी इस मार्ग का उपयोग करते हैं, जिससे यह क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमुख

केंद्र बना हुआ है। इस सीमा चौकी का सबसे अधिक महत्व अरबईन के अवसर पर देखने को मिलता है। यह दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें लाखों शिया श्रद्धालु इराक के पवित्र शहर करबला पहुंचते हैं। इस दौरान शलामचेह बॉर्डर से गुजरने वाले यात्रियों की संख्या बढ़कर लगभग 20 लाख (2 मिलियन) तक पहुंच जाती है। इस वर्ष अरबईन का आयोजन अगस्त की शुरुआत में होना है और श्रद्धालुओं की यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है। ईरान की मेहर समाचार एजेंसी के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि हमले के बावजूद श्रद्धालुओं की आवाजाही नहीं रुकी। सीमा पर राहत एवं बचाव अभियान चलने के साथ-साथ यात्रियों का आवागमन भी सामान्य रूप से जारी रहा।शलामचेह बॉर्डर केवल एक सीमा चौकी नहीं, बल्कि ईरान और इराक के बीच आर्थिक, धार्मिक और सामरिक संबंधों का महत्वपूर्ण केंद्र है। व्यापार, तीर्थयात्रा और क्षेत्रीय संपर्क के लिहाज से इसकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में होने वाली किसी भी घटना का असर न केवल दोनों देशों पर, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के सुरक्षा और भू-राजनीतिक परिदृश्य पर भी पड़ सकता है।

जॉर्डन में अमेरिकी 'थाड' मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 'पैट्रियट' सिस्टम किया तबाहः ईरान

एजेंसी
तेहरान । ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने गुरुवार को दावा किया कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर भारी नुकसान पहुंचाया है। आईआरजीसी के अनुसार, सटीक निशानों के जरिए उसने अमेरिकी थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट सिस्टम को तबाह कर दिया है। इन अहम अमेरिकी रक्षा प्रणालियों के अलावा उसने, सी-आरएएम रडार को भी निशाना बनाकर नष्ट करने की बात कही है। आईआरजीसी ने अपने आधिकारिक समाचार और जनसंपर्क पोर्टल 'सिपाह न्यूज' के हवाले से एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। आईआरजीसी का कहना है कि इसके अलावा अमेरिकी सैन्य अड्डे के ईंधन टैंकों और हेलीकॉप्टरों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए इस्तेमाल होने वाले हैंगर में भी हमले के बाद आग लग गई। इन हमलों से वे पूरी तरह नष्ट हो गए।आईआरजीसी ने अपने बयान में जॉर्डन की जनता को संबोधित करते

हुए अपना पक्ष भी स्पष्ट किया। उन्होंने सफाई में कहा, 'हमारी सैन्य कार्रवाई जॉर्डन की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करती, बल्कि देश में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी ही जॉर्डन की संप्रभुता का अतिक्रमण है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना एक वैध और आवश्यक कार्रवाई है।' हालांकि इस पर तत्काल जॉर्डन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले भी आईआरजीसी ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य परिसंपत्तियों पर हमले करने का दावा किया था।ईरान ने कहा कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों अल-अदीरी कैंप और अली अल-सलेम एयर बेस को निशाना बनाया। यह दावा ऐसे समय सामने आया है जब कुवैत की सेना ने अपने हवाई क्षेत्र में संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों की पुष्टि की है। कुवैती सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली दुश्मन ड्रोन खतरों का सामना कर रही है। सेना ने बताया कि रात में सुनाई देने वाले विस्फोट वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा इन ड्रोन को मार गिराने की कार्रवाई का हिस्सा थे।

इससे पहले, अमेरिकी सेना ने भी घोषणा की कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर उसने ईरान के खिलाफ लगातार 12वीं रात सैन्य कार्रवाई पूरी की है।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी बलों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें समुद्री सैन्य क्षमताएं, मिसाइल और ड्रोन भंडारण केंद्र, तटीय निगरानी ठिकाने तथा वायु रक्षा प्रणाली शामिल हैं।

अमेरिकी कोर्ट ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो मामले में तय की ट्रायल की तारीख, 1 जून 2027 से होगी सुनवाई

एजेंसी
न्यूयॉर्क । वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की सुनवाई मामले में जानकारी सामने आई है। एक अमेरिकी जज ने फैसला सुनाया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के मामले में 1 जून, 2027 से ट्रायल शुरू होगा। इस मामले में बुधवार (स्थानीय समय) को 15 मिनट की सुनवाई हुई। इस दौरान, जज एल्विन हेलरस्टीन ने दोनों पक्षों के वकीलों के कहने पर ट्रायल की तारीख तय की। मादुरो के वकील, बैरी पोलाक ने कहा कि वह पहले सॉवरेन इम्यूनिटी के आधार पर आरोप को चुनौती देंगे क्योंकि अगर वह सफल होता है, तो मादुरो को केस आगे नहीं लड़ना पड़ेगा।

बता दें, अमेरिकी मिलिट्री फोर्स ने 3 जनवरी को वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया और मादुरो और उनकी पत्नी को जबरदस्ती पकड़कर न्यूयॉर्क ले गए।न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी हमलों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को हैरान कर दिया है और दुनिया भर में इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को लेकर गंभीर चिंताएं जाहिर की गईं। 5 जनवरी को अपनी पहली पेशी के दौरान, मादुरो ने अपने खिलाफ लगे सभी अमेरिकी आरोपों में खुद को बेकसूर बताया। इन आरोपों में ड्रग तस्करी भी शामिल थी। मादुरो ने कोर्ट को बताया कि उन्हें काराकस स्थित घर से पकड़ा गया था।काराकस में पकड़े जाने के बाद से ही कपल को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में जेल में रखा गया है। इस बीच, मादुरो के वकील ने कोर्ट में जज पर आरोप खारिज करने के लिए दबाव बनाना जारी रखा है और तर्क दिया है कि अमेरिका, वेनेजुएला सरकार के फंड को उनकी कानूनी फीस देने से रोककर मादुरो के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इस बीच, मादुरो के वकील ने कोर्ट में जज पर आरोप खारिज करने के लिए दबाव बनाना जारी रखा है और तर्क दिया है।

यूएन में बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत बोला-संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों को मिले न्यायसंगत हिस्सा, तभी रुकेगी अस्थिरता

एजेंसी
संयुक्त राष्ट्र । भारत ने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के कथित शोषण का मुद्दा उठाया है। भारत का कहना है कि खनिज और अन्य प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध बलूचिस्तान का लंबे समय से दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण वहां के लोगों में इस्लामाबाद के खिलाफ असंतोष और विद्रोह की भावना बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा, 'यह प्रत्येक देश की जिम्मेदारी है कि तेल और गैस, खनिज, दुर्लभ धातुओं और बहुमूल्य संसाधनों से समृद्ध प्रांतों को उन संसाधनों से होने वाले लाभ में न्यायसंगत और समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करे।' उन्होंने कहा कि ऐसा करना केवल संबंधित देश के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में आंतरिक अस्थिरता और असुरक्षा को रोकने के लिए भी आवश्यक है। पी. हरीश ने

बिना पाकिस्तान का नाम लिए कूटनीतिक अंदाज में संकेत दिया कि यह स्थिति बलूचिस्तान पर लागू होती है। उन्होंने कहा, 'ऐसा न करने के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिनका प्रभाव हमारे क्षेत्र में भी देखा जा सकता है।' प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने के बावजूद बलूचिस्तान आज भी देश के सबसे गरीब प्रांतों में से एक बना हुआ है।इसकी वजह से बलूच के लोगों ने अपने प्रांत के योगदान में सही हिस्सा मांगते हुए विरोध प्रदर्शन किए और उनके बेरहमी से दबाने से बगावत को बढ़ावा मिल रहा है। हरीश ने चेतावनी दी, 'संसाधनों से भरपूर प्रांतों के शासन में सख्ती और सुरक्षा वाला तरीका मामलों को और खराब करता है। जो प्रांत संसाधनों से भरपूर हैं लेकिन विकास में पिछड़े हैं, वे असुरक्षा का केंद्र बन जाते हैं जो अपनी सीमाओं के बाहर, यहां तक कि पड़ोसी देशों में भी अस्थिरता फैलाते हैं।'उन्होंने कहा, 'यह अस्थिरता बाहरी लोगों द्वारा सीमा पार दखल और संसाधनों के दोहन को भी आकर्षित करती है, इससे स्थानीय समुदायों की शिकायतों के साथ अस्थिरता बढ़ती है।' 'नेचुरल रिसोर्स गवर्नेंस: शांति, सुरक्षा और खुशहाली की नींव' विषय पर उच्चस्तरीय खुली चर्चा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा, 'प्राकृतिक संसाधनों के गवर्नेंस और मैनेजमेंट की मुख्य जिम्मेदारी संप्रभु देशों की है।इसलिए, राष्ट्रीय स्वामित्व, कैपेसिटी-बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के केंद्र में रहना चाहिए।' खासकर अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, हथियारबंद समूहों और आतंकवादियों ने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए लड़ाई लड़ी है और इससे उनकी गतिविधियों को फंडिंग मिला है।

हूती विद्रोहियों का दावा, लाल सागर में दो सऊदी तेल टैंकरों पर हमला

एजेंसी
सना (यमन) । यमन के हूती समूह ने गुरुवार को कहा कि उसने लाल सागर में दो सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाकर एक मिलिट्री ऑपरेशन किया है। हूती ने दावा किया कि इन जहाजों ने समूह की हाल ही में घोषित समुद्री पाबंदियों का उल्लंघन किया है। समूह के अल-मसीरा टेलीविजन पर दिखाए गए एक बयान में, हूती मिलिट्री के प्रवक्ता याह्या सरेआ ने कहा कि हूती सेना ने ईएनसीईएलआईए और एलएएलईएलए नाम के टैंकरों को बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ-साथ ड्रोन का इस्तेमाल करके निशाना बनाया। सरेआ ने कहा कि इन जहाजों को इसलिए निशाना बनाया गया, क्योंकि उन्होंने सऊदी पोर्ट पर आने वाले जहाजों पर हूती की सेना द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किया था। उन्होंने दावा किया कि हमलों से दोनों टैंकरों में आग लग गई और उन्होंने अपने मकसद को कामयाबी से हासिल कर लिया। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, बयान में घटना की जगह के बारे में जानकारी नहीं दी गई और न ही हमले में हुए नुकसान का सबूत दिया गया और यह भी नहीं बताया गया कि कोई हताहत हुआ है या नहीं। इन दावों को अलग से वेरिफाई नहीं किया जा सका और सऊदी अधिकारियों की तरफ से भी इस हमले को लेकर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं आई है। इस बीच, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने कहा कि उसे सऊदी अरब के अल शुकाइक से लगभग 70 नॉटिकल मील दक्षिण-पश्चिम में एक टैंकर से जुड़ी घटना की रिपोर्ट मिली है।

ब्रिटेन के यूकेएमटीओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक चेतावनी में कहा कि संबंधित जहाज के कप्तान ने बताया है कि जहाज पर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल (गोला/मिसाइल जैसी वस्तु) से हमला हुआ, जिससे उसमें आग लग गई। चालक दल आग बुझाने की कोशिश कर रहा था।

हूती विद्रोहियों ने दो दिन पहले ही सऊदी अरब के बंदरगाहों के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद ही नए हमले हुए। यह दावा ऐसे समय आया है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है।

अमेरिका ने ईरान पर फिर बरसाए बम, जवाब में तेहरान ने दी तेल निर्यात रोकने की धमकी

एजेंसी
वाशिंगटन । अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर करीब 5:30 बजे नए हवाई हमले शुरू किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'यह मिशन ईरान की आम नाविकों और इलाके के पानी में चलने वाले कमर्शियल जहाजों को धमकाने की क्षमता को कम करता रहेगा।' न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर गोली चलाएगा, तो वह ईरान का पुल या पावर प्लांट तबाह कर देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'अब से, जब भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान होर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर गोली चलाएगा, चाहे वह मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी और डिवाइस या हथियार से हो, तो अमेरिका बमबारी करके एक पुल या पावर प्लांट को नष्ट कर देगा, जिसमें कैपिटल सिटी तेहरान के बगल में या उसमें मौजूद प्लांट भी शामिल हैं।' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जवाब में ईरान के मुख्य मिलिट्री कमांड खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है, तो ईरान पश्चिम एशिया से सभी तेल एक्सपोर्ट को रोक देगा और पूरे इलाके में तेल, गैस, बिजली और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा। ईरान ने कहा कि अमेरिका की लगातार धमकियां केवल इस युद्ध को क्षेत्र और उससे आगे तक फैलाने का कारण बनेंगी।

भारत-चीन रिश्तों में सकारात्मक प्रगति, मनीला में जयशंकर ने वांग यी से की व्यापक बातचीत

एजेंसी
मनीला । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ व्यापक बातचीत की। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री ने कहा, 'भारत और चीन के संबंध धीरे-धीरे सामान्य होने की दिशा में बढ़े हैं।' दोनों ने भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों, सीमा पर शांति एवं स्थिरता के साथ ही प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) की बैठक के इतर चीन के विदेश मंत्री एवं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की पोलित ब्यूरो के सदस्य वांग यी के साथ विस्तृत बातचीत की। बैठक की शुरुआत में अपने संबोधन में जयशंकर ने कहा, 'आपसे फिर मिलकर खुशी हुई। ईएएस और आसियान क्षेत्रीय मंच में हमारी भागीदारी न केवल सामूहिक रूप से विचारों के आदान-प्रदान का अवसर देती है, बल्कि इस द्विपक्षीय बैठक का भी अवसर प्रदान करती है।' उन्होंने कहा कि यह बैठक भारत-चीन संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर है। उन्होंने कहा, 'हम एक वर्ष पहले मिले थे और आप हाल ही में भारत भी आए थे। आज की यह बैठक हमारे संबंधों का आकलन करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार-विमर्श के लिए उपयोगी होगी। विदेश मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद दोनों देशों के संबंध धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अक्टूबर 2024 में कजान में हमारे नेताओं की बैठक के बाद भारत और चीन के संबंध धीरे-धीरे सामान्य होने की दिशा में बढ़े हैं। पिछले अगस्त में तियानजिन में उनकी मुलाकात ने इस दिशा को और मजबूत किया।' पक्ष जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर संबंध आपसी सम्मान, साझा हितों और एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं के सम्मान पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा, 'ऐसे संबंध बहुध्रुवीय एशिया और बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।' सीमा विवाद पर विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए अनिवार्य शर्त है। उन्होंने कहा, 'सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सामान्य संबंधों की पूर्वशर्त है। अक्टूबर 2024 से दोनों पक्ष इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमें इस पर आगे भी निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।' जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेदों को विवाद में नहीं बदलने देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हमारे नेताओं ने सहमति जताई थी कि मतभेद विवाद का रूप न लें। इन्हें उचित ढंग से संभालना कूटनीति की जिम्मेदारी है।' विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों का स्वागत किया। उन्होंने प्रत्यक्ष उड़ानों की बहाली, वीजा व्यवस्था में सुधार, कैलाश मानसरोवर यात्रा के दोबारा शुरू होने और सीमा व्यापार की बहाली जैसे कदमों का उल्लेख किया। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी कई मुद्दों पर काम किया जाना बाकी है। इनमें भारतीय कंपनियों के लिए निष्पक्ष बाजार पहुंच, व्यापार असंतुलन, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चिंताएं तथा सरकारी और जन-स्तर पर संपर्क को और सुगम बनाना शामिल है। जयशंकर ने ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता के दौरान चीन द्वारा दिए गए सहयोग की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में दोनों देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय महत्व के प्रमुख मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करना पहले से कहीं अधिक आवश्यक है।

page 1 and 8 July 24_page 1 Mar 25 final ds.qxd 7/24/2026 12:48 AM Page 2

आस्थावान बनने का ठेका ले रहे आस्था पर प्रहार करने वाले: सीएम

सिक्सलेन फ्लाईओवर सहित गोरखपुर को 995 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उपहार दिया मुख्यमंत्री ने, 813.52 करोड़ रुपये की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास*

गोरखपुर, 23 जुलाई।* मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था, सुरक्षा व विकास के मुद्दे पर कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने के दौरान आस्था पर प्रहार करने वाले सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले रहे हैं। कांग्रेस व सपा के लोगों के मुंह से आस्था के उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। सपा ने अपने शासन में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में बाधा डाली, रामभक्तों पर गोली चलवाईं। कांग्रेस ने भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, मंदिर आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा किया। ये लोग किस मुंह से आस्था की बात कर रहे हैं?

मुख्यमंत्री गुरुवार को गोरखपुर जिले के पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उक्त विकास कार्यों में टीपीनगर-पैडलेगंज मार्ग पर 2.6 किमी लंबे सिक्सलेन फ्लाईओवर सहित 813.52 करोड़ रुपये की 4

परियोजनाओं का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपये की 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस-सपा ने अपनी सरकारों में न केवल आस्था से खिलवाड़ किया, बल्कि युवाओं को नौकरी और रोजगार से वंचित किया, अन्नदाता किसानों का हक छीना। बहन-बेटियों व व्यापारियों की सुरक्षा पर संकट खड़ा किया। 2017 के पहले यूपी में आए दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी। होली, दुर्गापूजा, विजयदशमी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पर्वों पर दंगे होते थे, कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। अब इन्हीं दलों के लोग आस्था पर बड़े-बड़े हास्यास्पद उपदेश दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने 2017 के पहले इंसेफेलाइटिस को लेकर सरकारी उदासीनता, सुरक्षा और निवेश के बदतर हालात को लेकर भी कांग्रेस-सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंसेफेलाइटिस बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश की नियति बन चुकी थी। हजारों बच्चों की मौत हो गई, पर पिछली सरकारें कान में रुई डालकर सोती रहीं। उन्हें जनता की पीड़ा महसूस करने की फुर्सत नहीं थी। बच्चों, किशोरों व नौजवानों के जीवन के साथ कांग्रेस व सपा ने जितना शोषण व अत्याचार किया, उसे शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार ने नौजवानों को बेरोजगार करने का पाप किया। कभी नौकरी निकली भी तो उस पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा हो जाता था। सपा ने न सिर्फ नौकरियों पर डकैती डाली, बल्कि उसने नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जिससे युवाओं की पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, समृद्धि व भविष्य पर प्रश्न खड़े हुए। इन प्रश्नों का समाधान डबल इंजन सरकार ने निकाला। हमारी सरकार सुरक्षा के माहौल में विकास करने और बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष पूर्व गोरखपुर में भय का माहौल था। यह गुंडों, माफियाओं व मच्छर के लिए बदनाम था। कोई गोरखपुर नहीं आना चाहता था। कोई भी गीडा में निवेश करने को तैयार नहीं था। माफिया के भय से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदता था। लेकिन जब सुरक्षा का माहौल मिला तो बड़े पैमाने पर निवेश आया। अकेले गीडा में 50000 नौजवानों को नौकरी व रोजगार मिला है। अब हर व्यक्ति की पहली पसंद गोरखपुर में जमीन खरीदने और मकान बनवाने की होती है।मुख्यमंत्री ने कहा कि 2007 से 2017 तक प्रदेश की 29 चीनी मिलों को तत्कालीन कांग्रेस व सपा सरकारों ने बंद कर दिया। इनमें 21 चीनी मिलों को औने-पौने दामों पर बेचा गया। पडरौना चीनी मिल को महज 2 करोड़ में बेचा गया, जबकि उसके स्क्रेप का मूल्य इससे कई गुना अधिक था, जमीन की कीमत तो 200 करोड़ रुपये थी।सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने 9 वर्षों के दौरान बिना भेदभाव 9 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। अब नौकरियों में बिना भेदभाव चयन होता है और इसमें गोरखपुर के नौजवानों को भी पर्याप्त अवसर मिल रहा है। एक जिला-एक उत्पाद योजना से पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित किया गया। सवा तीन करोड़ युवाओं, कारीगरों ने अपने उद्यम प्रारंभ किए। 65 लाख नौजवानों को निजी निवेश के माध्यम से नौकरी व रोजगार प्राप्त हुआ है। 2017 के पहले प्रदेश में यह संभव नहीं था।मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छा कार्य होता है। जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उसके सकारात्मक और प्रगतिशील परिणाम आते हैं। डबल इंजन सरकार आने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश से इंसेफेलाइटिस को समाप्त कर दिया गया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने हैं। गोरखपुर में एम्स बना और बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी चिकित्सा का बेहतरीन केंद्र बन चुका है। गोरखपुर में 1990 से बंद खाद कारखाना चालू हो चुका है। इससे किसानों को समय से खाद उपलब्ध हो रही है। किसानों को बीज और खाद समय पर उपलब्ध हो तो उत्पादन अच्छा होता है। जब किसान खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। गोरखपुर में मुक्तेश्वरनाथ मंदिर का पुनरोद्धार हो गया है, झारखंडी महादेव मंदिर के पुनरोद्धार के लिए भी प्रस्ताव मांगा गया है।

स्थानीय समाचार

RTI से बड़ा खुलासा- सांबा वन प्रभाग के पुरमंडल ब्लॉक में मजदूरी के नाम पर फर्जीवाड़े के आरोप

सांबा। जम्मू-कश्मीर के सांबा वन प्रभाग के पुर्मंडल ब्लॉक से जुड़े एक मामले में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर कथित अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप सामने आए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मस्टर रोल में ऐसे कई लोगों के नाम दर्ज किए गए, जिन्होंने कथित तौर पर कोई दिहाड़ी या मजदूरी का काम किया ही नहीं।

RTI से प्राप्त दस्तावेजों में सामने आए तथ्यों के अनुसार, मस्टर रोल में दर्ज कुछ लोग नियमित रूप से किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं, जबकि कुछ नाम ऐसे छात्रों के बताए गए हैं, जो स्कूल या कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बावजूद इन लोगों के नाम कथित तौर पर मजदूरी से जुड़े मस्टर रोल में दर्ज किए गए।

मामले को और गंभीर बनाता है यह आरोप कि मस्टर रोल में दर्ज कई नाम वन विभाग के कर्मचारियों के रिश्तेदारों या पारिवारिक सदस्यों से संबंधित हैं। यदि RTI के जरिए सामने आई यह जानकारी सही पाई जाती है, तो यह सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर और सार्वजनिक धन के संभावित दुरुपयोग का मामला हो सकता है।

उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आरोप है कि जिन लोगों ने वास्तव में दिहाड़ी या मजदूरी का काम नहीं किया, उनके नाम पर मस्टर रोल तैयार किए गए। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इन नामों के आधार पर सरकारी धन का भुगतान किया गया और यदि किया गया तो वह राशि किसके खाते में पहुंची?

मामले में अब निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग उठ रही है। मांग की गई है कि मस्टर रोल में दर्ज सभी नामों का भौतिक सत्यापन कराया जाए और यह जांच की जाए कि संबंधित व्यक्तियों ने वास्तव में काम किया था या नहीं। साथ ही, भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड, बैंक खातों और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो सरकारी धन के कथित दुरुपयोग में शामिल अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, सार्वजनिक धन की वसूली सुनिश्चित करने की मांग भी उठ रही है।

हालांकि, उपलब्ध इन्फोग्राफिक में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि या संबंधित वन विभाग के अधिकारियों का पक्ष शामिल नहीं है। इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित विभाग का पक्ष सामने आना आवश्यक है।

मुख्य सवाल

- मास्टर रोल में दर्ज लोगों ने वास्तव में काम किया था या नहीं?
- यदि काम नहीं किया, तो उनके नाम मस्टर रोल में कैसे दर्ज हुए?
- क्या इन नामों के आधार पर सरकारी भुगतान किया गया?
- भुगतान की राशि किसके खातों में गई?
- क्या मस्टर रोल तैयार करने और भुगतान स्वीकृत करने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच हुई?
- क्या विभागीय कर्मचारियों के रिश्तेदारों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाया गया?

RTI से सामने आए इन तथ्यों ने सांबा वन प्रभाग के पुर्मंडल ब्लॉक में पारदर्शिता और सरकारी धन के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे अहम बात यह होगी कि संबंधित विभाग और प्रशासन इन आरोपों की जांच कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने कब तक रखते हैं।

भारी बारिश के बाद झेलम नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा लेकिन जलस्तर खतरे के निशान से नीचे

श्रीनगर, 23 जुलाई (हि.स.)। कश्मीर में भारी बारिश के बाद गुरुवार को झेलम नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा जिसके चलते बाढ़ नियंत्रण अधिकारियों ने इस पर कड़ी निगरानी रखी। हालांकि तीनों प्रमुख जलमापी केंद्रों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे ही रहा।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार सबसे अधिक जलस्तर संगम में दर्ज किया गया जहां शाम करीब 5 बजे नदी का जलस्तर 19.5 फीट तक पहुंच गया जबकि खतरे का निशान 25 फीट है। श्रीनगर के राम मुंशीबाग में शाम करीब 5 बजे नदी का जलस्तर 17 फीट तक पहुंच गया जो खतरे के निशान 21 फीट से नीचे रहा। आशम में नदी के निचले हिस्से में शाम करीब 5 बजे जलस्तर 10 फीट तक पहुंच गया जो खतरे के निशान 16.5 फीट से काफी नीचे है। विभाग के हाइड्रोग्राफ से पता चला है कि बुधवार देर रात से गुरुवार सुबह तक संगम में जलस्तर में सबसे तेज वृद्धि हुई और नदी का जलस्तर दिन भर बढ़ता रहा। राम मुंशीबाग और आशम में भी जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की गई हालांकि यह वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी गति से हुई। अधिकारियों ने जलस्तर में वृद्धि का कारण लगातार बारिश और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से बहकर आने वाले पानी को बताया।

मुख्य सचिव ने सरकारी आवासीय कॉलोनियों के लिए चंडीगढ़ की ऑनलाइन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्रणाली अपनाने की समीक्षा की

श्रीनगर, 2मुख्य सचिव अतल डुल्लू ने आज आवास एवं शहरी विकास विभाग (एच एंड यूडीडी) की बैठक में चंडीगढ़ के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस) को जम्मू-कश्मीर की सरकारी आवासीय कॉलोनियों के प्रबंधन के डिजिटलीकरण के लिए अपनाने की प्रगति की समीक्षा की।

इस पहल का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारी आवासीय कॉलोनियों के आवंटियों को पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना है।

बैठक में आवास एवं शहरी विकास विभाग की आयुक्त सचिव, जम्मू नगर निगम के आयुक्त, श्रीनगर नगर निगम के आयुक्त, जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) के उपाध्यक्ष, श्रीनगर विकास प्राधिकरण (एसडीए) के उपाध्यक्ष, एनआईसी जम्मू-कश्मीर के राज्य सूचना अधिकारी, जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय जम्मू एवं कश्मीर के निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एनआईसी चंडीगढ़ के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव ने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं में तकनीक का अधिकतम उपयोग समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाना आवास एवं शहरी विकास विभाग में डिजिटल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि यह ऑनलाइन प्रणाली संपत्ति से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी, नागरिकों और सरकारी कार्यालयों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को कम करेगी, मामलों के निपटारे में लगने वाला समय घटाएगी तथा जम्मू-कश्मीर की सरकारी आवासीय कॉलोनियों के आवंटियों को अधिक सुविधा प्रदान करेगी। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को एनआईसी चंडीगढ़ और एनआईसी जम्मू-कश्मीर के साथ समन्वय स्थापित कर परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सॉफ्टवेयर के आवश्यक अनुकूलन, आंकड़ों की शुद्धता, व्यापक परीक्षण और सार्वजनिक उपयोग से पहले सुरक्षा ऑडिट पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने परियोजना के सुचारु संचालन के लिए संबंधित कर्मचारियों के क्षमता निर्माण की आवश्यकता भी रेखांकित की। बैठक की शुरुआत में आवास एवं शहरी विकास विभाग की आयुक्त सचिव मनदीप कौर ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम की प्रमुख विशेषताओं तथा अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है और ऑनलाइन संपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली स्वामित्व और लीज से संबंधित सेवाओं के लिए शुरुआत से लेकर अंतिम निस्तारण तक पूरी तरह डिजिटल मंच उपलब्ध कराती है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यकुशलता और नागरिकों के लिए सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होती है। बैठक के दौरान एनआईसी चंडीगढ़ की टीम ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम का लाइव प्रदर्शन किया तथा इसके विभिन्न मॉड्यूल, कार्यप्रणाली और संचालन प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी।

तारिगामी ने पर्यावरण समिति की बैठक की अध्यक्षता की

ईको-टूरिज्म नीति की समीक्षा, सतत विकास के लिए प्रत्येक पर्यटन स्थल का मास्टर प्लान तैयार करने पर दिया जोर

श्रीनगर, 23 जुलाई । विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज विधानसभा परिसर में पर्यावरण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर जम्मू-कश्मीर में ईको-टूरिज्म नीति के क्रियान्वयन तथा पर्यावरण संरक्षण उपायों की समीक्षा की।

बैठक में विधायक प्रोफेसर घरू राम, डॉ. सज्जाद शफी, शौकत हुसैन गनी और जावेद रियाज बेदार भी उपस्थित थे।

समिति को बताया गया कि जम्मू-कश्मीर की ईको-टूरिज्म नीति अंतिम चरण में है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यटन गतिविधियों का नियमन तथा स्थानीय समुदाय आधारित सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी ढांचा तैयार करना है।

समिति के अध्यक्ष ने जम्मू-कश्मीर के सभी ईको-टूरिज्म स्थलों के लिए अलग-अलग मास्टर प्लान तैयार करने पर विशेष जोर दिया, ताकि योजनाबद्ध विकास, पर्यटकों की वहन क्षमता का नियमन, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन तथा जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

समिति ने निर्देश दिया कि इन मास्टर प्लानों को विशेषज्ञों, स्थानीय समुदायों तथा अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श कर अंतिम रूप दिया जाए, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन विकास सुनिश्चित हो सके।

बैठक में प्रमुख ईको-टूरिज्म स्थलों, पिछले पांच वर्षों की आय, तथा पर्यावरणीय चुनौतियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

समिति अध्यक्ष ने पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों को प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित करने सहित उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की।

पर्यटन विभाग ने बताया कि 卐ट्रैवल फॉर लाइफ- टूरिज्म फॉर टुमॉरो卐 तथा 卐स्वच्छता ही सेवा卐 जैसे राष्ट्रीय अभियानों के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा दूधपथरी और यूसमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर नियमों के पालन को और सख्त किया गया है। समिति ने सभी पर्यटन विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्लास्टिक मुक्त अभियानों और उनके क्रियान्वयन की स्थलवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। समिति ने पर्यटन विकास प्राधिकरणों द्वारा पर्यावरण मानकों के पालन, सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) तथा प्रस्तावित मिनी एसटीपी, जल गुणवत्ता, प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता और पर्यटन मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। बैठक में जम्मू के तवी गोल्फ क्लब, आर्द्रभूमियों के क्षरण, पर्यटन स्थलों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर विशेष चिंता व्यक्त की गई।

बांदीपोरा प्रशासन स्कूल इको क्लबों के साथ मिलकर करेगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य

बांदीपोरा, 23 जुलाई। उपायुक्त बांदीपोरा इंदु कंवल चिब ने आज जिले के सभी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के इको क्लब प्रभारी तथा एनएमबीएचएसएस और जीएचएसएस बांदीपोरा के विद्यार्थियों के साथ प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रभावी कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए जिले के सभी इको क्लबों को सक्रिय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने इको क्लबों की गतिविधियों की नियमित निगरानी करने तथा पर्यावरण संरक्षण अभियानों का नेतृत्व करने के लिए समर्पित विद्यार्थियों और शिक्षकों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा स्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण, कचरे में कमी और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देने में इको क्लबों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। व्यावहारिक सीख को मजबूत बनाने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उपायुक्त ने प्रतिभागियों से नॉलेज सेंटर, जल शक्ति केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम की महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित कैफेटेरिया तथा प्रोजेक्ट इंसानियत जैसी जिला स्तरीय पहलों का अध्ययन भ्रमण करने का आग्रह किया, ताकि वे टिकाऊ और सामुदायिक भागीदारी वाले प्रयासों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर उपायुक्त ने इको क्लब प्रभारियों और विद्यार्थियों से अपने घरों से ही शून्य अपशिष्ट जीरो वेस्ट की अवधारणा अपनाकर उदाहरण प्रस्तुत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की स्थायी शुरुआत व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयासों से होती है तथा सभी से बांदीपोरा की प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिकी के संरक्षण में सक्रिय योगदान देने की अपील की।

उपराज्यपाल सक्सेना ने ऐतिहासिक लेह ओल्ड टाउन के विरासत आधारित कायाकल्प परियोजना की आधारशिला रखी

आधुनिक शहरी सुविधाओं के साथ लद्दाख की ऐतिहासिक विरासत और पारंपरिक वास्तुकला को मिलेगा नया संरक्षण

लेह, 23 जुलाई। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज ऐतिहासिक लेह ओल्ड टाउन के विरासत आधारित व्यापक कायाकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए यहां आधारभूत संरचना उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण परियोजना की आधारशिला रखी। यह परियोजना लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित रखते हुए आधुनिक शहरी सुविधाओं के विकास की दिशा में एक नया अध्याय साबित होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी, विरासत भी卐 के विजन से प्रेरित इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक नागरिक सुविधाओं को विरासत संरक्षण के साथ संतुलित ढंग से विकसित करना है, ताकि लेह ओल्ड टाउन अपनी ऐतिहासिक धरोहर, विशिष्ट वास्तुकला और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक शहरी आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो सके।

परियोजना के तहत पानी की आपूर्ति, सीवरेज, बिजली, दूरसंचार और अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की भूमिगत व्यवस्था के लिए बहुउद्देश्यीय ट्रेंच एवं कॉमन यूटिलिटी डक्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पैदल यात्रियों के अनुकूल मार्ग, विरासत के अनुरूप सड़क सौंदर्यीकरण, बेहतर जल निकासी व्यवस्था, सजावटी प्रकाश व्यवस्था, पारंपरिक शैली के दिशा-सूचक संकेतक, पर्याप्त पार्किंग, हरित क्षेत्र, बैठने की व्यवस्था, उन्नत सार्वजनिक सुविधाएं तथा समग्र शहरी सौंदर्य को विकसित किया जाएगा, जिससे यह क्षेत्र अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक बनेगा। उपराज्यपाल का कार्यभार

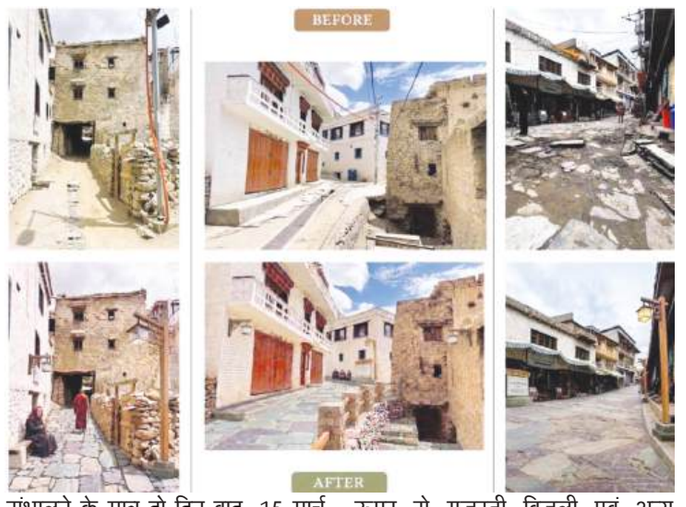

संभालने के मात्र दो दिन बाद, 15 मार्च को श्री सक्सेना ने लेह ओल्ड टाउन और लेह मुख्य बाजार का पैदल दौरा कर जमीनी स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि लेह ओल्ड टाउन, जो लद्दाख की ऐतिहासिक पहचान का केंद्र है, अनियंत्रित निर्माण, ऊपर से गुजरती बिजली एवं अन्य उपयोगिता केबलों, सड़कों के बीच से गुजरने वाली नालियों, बार-बार सड़क कटाई, सार्वजनिक सुविधाओं की कमी तथा बिगड़ते शहरी ढांचे जैसी कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिससे सदियों पुराने इस नगर की ऐतिहासिक पहचान और सौंदर्य प्रभावित हो रहा है।

दौरे के तुरंत बाद उपराज्यपाल ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए थे कि लेह ओल्ड टाउन के विरासत आधारित कायाकल्प के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाए, जिसमें प्रत्येक विकास कार्य उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए आधुनिक नागरिक सुविधाओं को शामिल करे।

उपराज्यपाल ने बताया कि यह परियोजना उनके लिए एक विशेष महत्व का सपना थी, जिसे साकार करने के लिए लगभग चार महीने तक विस्तृत योजना, विशेषज्ञों से विचार-विमर्श और डिजाइन तैयार करने का कार्य किया गया। अब यह परियोजना आकार ले चुकी है और इसे सितंबर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 卐विकास भी, विरासत भी के विजन का व्यावहारिक उदाहरण है, जिसमें विकास और विरासत संरक्षण दोनों साथ-साथ आगे बढ़ते हैं